

# परिवर्तन का दौर: विकास, रोजगार और मांग में तेजी लाने का मुख्य प्रेरक निजी निवेश

# 01

अध्याय

पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ऊपर से नीचे की ओर हितलाभ संचरण के कई रास्ते खोल कर, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि समष्टि आर्थिक स्थिरता के लाभ पिरामिड के निचले स्तर तक पहुंचें। भारत को वर्ष 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए वास्तविक संदर्भ में 8% की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कायम रखने की जरूरत है जैसा प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव विशेषकर उच्च विकास दर वाले पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्थाओं का अनुभव यह सुझाव देता है कि ऐसा विकास केवल बचत, निवेश और निर्यातों के सद् चक्र से संचालित विकास मॉडल से ही बनाए रखा जा सकता है जिसे अनुकूल जनांकीय दौर से मदद मिले। निवेश विशेषकर निजी क्षेत्र से आया निवेश वह महत्वपूर्ण कारक है जो मांग को संचालित करता है, क्षमता निर्माण करता है, श्रम उत्पादकता में वृद्धि करता है, नई प्रौद्योगिकी का आगम सुसाध्य बनाता है, सृजनात्मक ध्वंस करता है और नौकरियां सृजित करता है। निवेश विशेष रूप से निजी निवेश के माध्यम से ही हो सकता है। निर्यात विकास मॉडल के एक अभिन्न अंग के रूप में होना चाहिए क्योंकि अंतिम मांग के प्रेरक के रूप में घरेलू उपभोग अधिक बचत की राह में रोड़ा अटकाता है। उसी तरह से रोजगार सृजन इस सद् चक्र से प्रेरित होता है। हालांकि अक्सर यह दावा किया जाता है कि निवेश नौकरियों का स्थान ले लेते हैं, यह तभी सत्य होता है जब इसे किसी विशिष्ट कार्यक्रमलाप की परिधि में देखा जाता है। जब इसे समस्त मूल्य श्रृंखला के संदर्भ में जांचा जाता है, तब पूंजीगत निवेश रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन, अनुसंधान/विकास तथा आपूर्ति श्रृंखला से नौकरियां सृजित होती हैं।

समीक्षा परंपरागत ऐंग्लो-सैक्सोन संतुलनवादी दृष्टिकोण का त्याग कर भारत के लिए एक ऐसे संवृद्धि प्रतिमान की वकालत कर रही है जिसमें सद्चक्र या दुश्चक्र ही चलता रहता है। यह पारंपरिक दृष्टिकोण से दो प्रकार से भिन्न है। एक तो हम संतुलन को एक आधारभूत संकल्पना मानने से दूर हट रहे हैं क्योंकि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से इस संकल्पना पर बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं। दूसरे, परंपरागत प्रतिमान रोजगार सृजन, मांग, निर्यात तथा आर्थिक संवृद्धि को पृथक-पृथक समस्याएं मान कर उनके समाधान के प्रयास करता है। किन्तु इन समष्टि आर्थिक घटनाओं में महत्वपूर्ण अंतर संबंध विद्यमान होते हैं। समीक्षा ऐसे समष्टि आर्थिक चक्र के केन्द्रीय महत्व की कल्पना कर रही है जो सारी अर्थव्यवस्था में एक सद्चक्र को संप्रेरित कर सकता हो। समीक्षा निवेश को ऐसा निर्णायक चालक मानती है, अतएव आंकड़ों को सार्वजनिक पदार्थ का रूप देकर, विधिक सुधारों पर आग्रह करके, नीतियों में सुसंगति सुनिश्चित करके तथा व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार परिवर्तन को संप्रेरित करते हुए समीक्षा एक स्वपोषी सद्चक्र को संबल प्रदान करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस विचार

के मुख्य घटकों में उन नीतियों पर ध्यान केन्द्रित करना शामिल है जो सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों को अधिक रोजगार सृजक और उत्पादक बनाएं, पूंजी की लागत घटाएं तथा निवेश पर जोखिम-प्रतिप्राप्ति के समप्रत्ययन को तर्क संगत बनाएं।

## पिछले पांच वर्ष: उपलब्धियां

### व्यापक आर्थिक स्थिरता

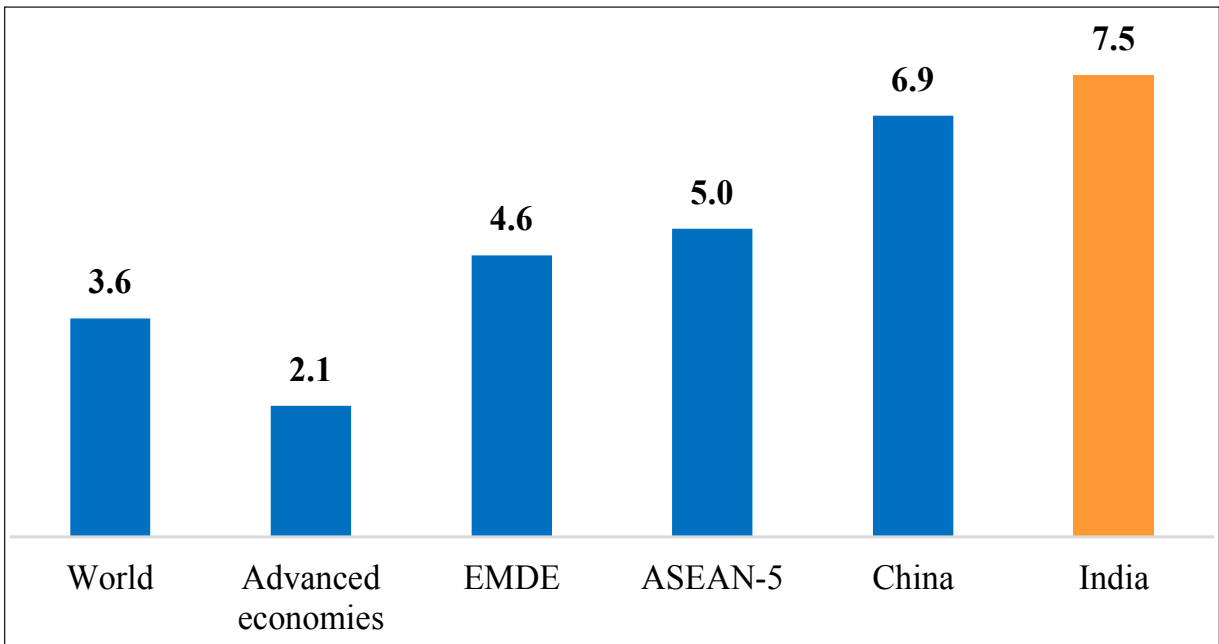
1.1 समष्टि आर्थिक स्थिरता विश्व उत्पादन 2014 और 2018 में भी 3.6 प्रतिशत बढ़ा। इस अवधि में जब विश्व में कोई ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई दिया है, फिर भी, भारत ने कई बड़े-बड़े कदम उठाए हैं। भारत चीन से उच्च दर पर संवृद्धि करने वाली और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इसने विश्व में तेजी से संवृद्धि विकास करने वाली अर्थव्यवस्था होने का तमगा हासिल किया है (चित्र-1)। महत्वपूर्ण रूप से विकास की इस गति की समष्टि स्थिरता को पुनः प्राप्त करने के लिए कड़े कदम उठाते हुए बरकरार रखना होगा।

1.2 इन पांच वर्षों में औसत मुद्रास्फीति पिछले पांच वर्षों की मुद्रास्फीति की दर के आधे से कम है, देश

के स्वतंत्रता पश्चात् के इतिहास में ये निम्न स्तर पर है। चालू खाता घाटा (सीएडी) नियंत्रण के भीतर है और विदेशी विनिमय उच्चतम रिजर्व स्तर पर है।

1.3 यह न केवल एकबारगी समामेलन था बल्कि इससे एक नए संस्थागत फ्रेमवर्क का निर्माण संभव हुआ है। दो प्रतिशतांक के बैंड के साथ 4 प्रतिशत की प्रमुख मुद्रास्फीति के लक्ष्य के अधिदेश सहित फरवरी, 2015 में भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), के बीच एक करार का पालन करते हुए एक वित्तीय नीतिगत समिति (एनपीसी) गठित की गई थी। मुद्रास्फीति नियंत्रण में यह फ्रेमवर्क बहुत सफल बन गया है। अप्रैल, 2015 से जब एनपीसी की पहली बैठक का आयोजन किया गया था, मासिक शीर्ष मुद्रास्फीति एक माह को छोड़ कर, हमेशा बैंड के भीतर रही है।

चित्र 1: भारत और विश्व में जीडीपी में वृद्धि



डाटा स्रोत: वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अप्रैल, 2019 आईएमएफ।

टिप्पणी: (1) ईएमडीई-उभर रही बाजार तथा विकासशील अर्थव्यवस्था; (2) आसियान-5 के पांच देश: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्स, थाइलैंड और वियतनाम।

1.4 सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) पर भी यह अनुशासन लागू किया गया। 2003 का राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम जिसने 2016 में एक नया जीवन प्राप्त किया है, यह 3 प्रतिशत के संभावित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जीएफडी/जीडीपी अनुपात के पथ को निर्धारित करता है। 2013-14 में अनुपात 4.5 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 3.4 प्रतिशत हो गया है, अन्य समष्टि स्थिरता सूचकांकों में भी इसी तरह का सुधार हुआ है।

### हितलाभी केन्द्रित एवं लक्षित प्रदायगी

1.5 समष्टि अर्थव्यवस्था में स्थिरता को पुनः लागू करने के अलावा, सरकार मूल सुरक्षोपाय तथा सामाजिक आर्थिक विकास को निचले तबके तक पहुंचाने हेतु विकास के लाभ का फायदा उठाने के लिए उपायों के जरिए गरीब लोगों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के अंतिम छोर पर भी ध्यान दे रही है। आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, प्रसुविधाओं और सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) अधिनियम, 2016 की घोषणा एक ऐसी पहल थी कि जिसने इस वर्ग के लिए बड़े रास्ते खोले हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट संख्या प्रदान करके अब सरकार लक्षित सहायता प्रदान करने में सक्षम हो गई है। वर्तमान में देश की 90 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या आधार के कवरेज में आती है।

1.6 एक अन्य पथ प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) की वित्तीय समावेशन पहल ने खोला है। बैंक खातों को आधार तथा मोबाइल नम्बरों से जोड़े जाने के बाद एक जैम (जनधन-आधार, मोबाइल) त्रिमूर्ति तैयार की गई, जो आशायित लाभार्थियों को सीधा लाभ अंतरण सुरक्षित बनाती है। वर्तमान में पीएमजेडीवाई के अंतर्गत खोले गए 35 करोड़ से अधिक बैंक खातों में एक ट्रिलियन के करीब धनराशि जमा हुई है। जैम त्रिमूर्ति ने लगभग 7.3 ट्रिलियन संचयी अंतरण करने में सक्षम बनाया है। वर्तमान में 370 नकद आधारित योजनाओं के माध्यम से 55 केन्द्रीय मंत्रालय डीबीटी तंत्र के अंतर्गत लाभार्थियों को धन अंतरित करते हैं। वास्तव में, समीक्षा के खंड I अध्याय 10 में इसके सावधानीपूर्वक साक्ष्य प्रदान किए गए हैं।

1.7 डीबीटी के अंतर्गत कार्यान्वित की गई प्रमुख

योजनाओं में एमजीएनआरईजीएस (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना), एनएसयूपी (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम), पीएमएवाई-जी (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण), और विभिन्न छात्रवृत्तियां तथा उर्वरक सब्सिडी योजनाएं शामिल हैं। अंतिम छोर पर अदायगी के लिए एक प्रमुख पहल प्रधानमंत्री उज्वला योजना (पीएमयूवाई) थी जो 2016 में आरंभ हुई थी। पीएमयूवाई में 1600 रुपए प्रति कनेक्शन की सहायता के साथ बीपीएल (गरीबी की रेखा से नीचे) परिवारों को 3 वर्ष की अवधि के भीतर 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाने का मूल लक्ष्य निर्धारित किया गया था। आज की तारीख तक 700 से अधिक जिलों में रहने वाली महिलाओं को 70 मिलियन से अधिक पीएमयूवाई-एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं। 2018 में एक मूलभूत सुरक्षोपाय प्रदान करने का एक अन्य प्रयास आयुष्मान भारत योजना (एबीवाई) के माध्यम से आरंभ किया गया था, जिसमें 100 रुपए प्रति माह के नाममात्र प्रीमियम पर 100 मिलियन बीपीएल परिवारों में प्रत्येक को नकद रहित उपचार के लिए 5,00,000 रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। आज की तारीख तक इस योजना में 15,000 से ज्यादा अस्पतालों का पैनेल बन चुका है, जिनमें 346 मिलियन सूचीबद्ध लाभार्थियों से लगभग 2.6 मिलियन व्यक्ति चिकित्सा लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

### अवसंरचना

1.8 भौतिक अवसंरचना के निर्माण में 2014-19 के दौरान महत्वपूर्ण रूप से तब तेजी आई है जब अप्रैल, 2018 में, अन्ततः भारत के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई साथ ही प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का निर्माण कार्य, तेज गति से चला है और पिछले पांच वर्षों में निर्मित सड़कों 132,000 कि॰मी॰ की मौजूदा राजमार्ग लंबाई का 20 प्रतिशत से अधिक अंग है। देश में टियर 3 तथा टियर 4 नगरों की उड़ान सेवा से संपर्क बढ़ाकर क्षेत्रीय संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए 2017 में उड़ान योजना आरंभ की गई थी। 40 लाख अतिरिक्त सिटिंग क्षमता का निर्माण करते हुए उड़ान फ्लाइटों के साथ 30 असेवित तथा सेवाधीन एयरपोर्टों को मुख्यधारा में लाया गया है। यह योजना पहाड़ी क्षेत्रों तथा द्वीपों में हेलीकॉप्टर सेवाओं में भी महत्वपूर्ण वृद्धि में लगी है,

इसके लिए 31 हेलीपैटर्स लगाए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की अवसंरचना पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है और बड़े पुलों के निर्माण, रेलवे/राजमार्गों का विस्तार करने से कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार आया है। दिसम्बर, 2018 में असम में 4.94 कि॰मी॰ लंबे बोगीवील पुल का उद्घाटन किया गया जो एशिया का दूसरा सबसे लम्बा रेल-सह-सड़क पुल है।

### संघीकरण

1.9 चौदहवें वित्त आयोग द्वारा केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने से राजकोषीय संघवाद में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यद्यपि राज्यों को केन्द्रीय अनुदानों में कटौती भी देखी गई है, फिर भी, राज्यों को स्वतंत्र रूप से, अपने राजस्व तथा व्यय का प्रबंध करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

1.10 जुलाई, 2017 में जीएसटी (माल एवं सेवाकर) का आरंभ किया जाना, केन्द्र-राज्य और अंतर-राज्य संबंधों को नया प्रतिमान उपलब्ध कराएगा। जीएसटी परिषद् का अनुभव श्रम तथा भूमि विनियमन जैसे अन्य कुछ क्षेत्रों में सहकारी संघवाद के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख जानकारी प्रदान करता है। नीति आयोग ने विकास चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त रूप से नीतिगत तरीके से राज्य तथा केन्द्रीय सरकार दोनों से दल गठित करके संस्थागत सहकारी संघवाद में मदद की है। राज्य अपने प्रमुख कार्य-निष्पादन सूचकों (केपीआई) में सुधार लाने के लिए एक अनुकूल प्रतिस्पर्द्धा में शामिल रहे हैं।

### कार्पोरेट बहिर्गमन

1.11 2016 में, जब दिवालियापन और दिवालिया संहिता (आईबीसी) लागू कर पूर्व प्रचलित विविध प्रक्रियाओं के निरसन/संशोधन द्वारा एक एकल कानून में दिवालियापन समाधान प्रक्रिया को मजबूत बनाया

गया है। दिवालियापन तथा दिवालिया संबंधी मामलों के समाधान के लिए आईबीसी में एक समय-सीमा निध रित है, जिसके भीतर, एक चूककर्ता की परिसंपदाओं को ऋणदाता संस्थानों से लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए नीलाम किया जाता है। 2017 से आईबीसी के संचालन के बाद से, इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अनर्जक परिसंपदाओं की संख्या में काफी कमी आई है। समाधान अथवा दिवालियेपन से ऋणदाताओं द्वारा बड़ी संख्या में धनराशियों की वसूलियों के अतिरिक्त, बहिर्गमन के लिए एक फ्रेमवर्क की प्रस्तावना ने देश की समग्र व्यापार संस्कृति में सुधार किया है। इस विषय का विस्तार समीक्षा के खंड II के अध्याय-3 में देखा जा सकता है।

### आगामी पांच वर्ष: संवृद्धि और रोजगार सृजन की कार्ययोजना

1.12 पिछले पांच वर्षों में समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्रिक आधारों की रचना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था नई करवट लेने को तैयार है ताकि आर्थिक संवृद्धि, रोजगार सृजन तथा निर्यात को अगले स्तर तक पहुंचाया जा सके। इस प्रयोजन से, समीक्षा ने एक कार्य-योजना प्रस्तुत की है।

### विकास की ओर उन्मुख

1.13 जैसाकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है, भारत का उद्देश्य 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, जो भारत को विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। 4 प्रतिशत की मुद्रास्फीति के साथ, भारतीय रिजर्व बैंक की रूपरेखा ने जीडीपी में 8 प्रतिशत<sup>1</sup> की वास्तविक वार्षिक वृद्धि दर को अपेक्षित माना है। एक आदर्श अर्थव्यवस्था के वे कौन से घटक हैं, जो ऐसी संवृद्धि सृजित कर सकते हैं?

1.14 इस मुख्य प्रश्न को समझने के लिए हमें वैश्विक रूप से देशों में आर्थिक संवृद्धि के प्रचालकों की जांच

<sup>1</sup> विभिन्न मॉडलिंग संभावनाओं में से, भारत में कुल कारक उत्पादकता में संभावित 0.7 प्रतिशत की वृद्धि की अमेरिका से तुलना की जाती है और एक स्थिर वास्तविक विनिमय दर प्रभावी होती है। यह बाद में मार्च, 2025 में 75 रुपए प्रति यूएसडी की विनिमय दर में रूपांतरित होती है, जिसका तात्पर्य है कि मार्च भारतीय अर्थव्यवस्था में 375 लाख रुपए की जीडीपी होनी चाहिए। 4 प्रतिशत की मुद्रास्फीति से युक्त जीडीपी के लिए एक 8 प्रतिशत की वास्तविक विकास दर इस जीडीपी को संभव बनाएगी। जबकि 8 प्रतिशत वास्तविक जीडीपी दर की प्राप्ति के लिए अपेक्षित निर्यात वृद्धि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में हास की आवश्यकता हो सकती है, हमें मुद्रा के हास पर ध्यान देने के बजाय उत्पादकता में वृद्धि से निर्यात वृद्धि पर जोर देना चाहिए।

करनी होगी। वर्तमान समय में, अपनी चार दशकों की लम्बी अवधि से विस्फोटक संवृद्धि के साथ चीन की आर्थिक संवृद्धि उत्कृष्ट है। ब्रिटेन और पश्चिमी यूरोप में युद्ध के बाद आर्थिक विस्तार के कारण अपनी अर्थव्यवस्था में उच्च संवृद्धि दर पाई थी। जापान ने 1950 से 1973 तक लगभग 10 प्रतिशत की औसत दर से संवृद्धि की जबकि इसकी तुलना में, इस अवधि के दौरान चीन की संवृद्धि दर की गति उतनी नहीं थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताईवान ने 1980 तक 7 प्रतिशत से अधिक की द्रुत गति की संवृद्धि दर सफलतापूर्वक कायम रखी थी।

### “मुख्य प्रेरक” के रूप में बचत, निवेश, निर्यात तथा संवृद्धि का सद् चक्र

1.15 वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए हाल के समय में, चीन और पूर्वी एशिया में जो उच्च संवृद्धि दर है जिसे केवल हितकारी जनांकीय चरण द्वारा उत्प्रेरित तथा समर्थित बचत, निवेश तथा निर्यात के एक सद् चक्र द्वारा एक विकास मॉडल चलाकर बरकरार रखा गया है। जैसाकि हमने नीचे विस्तार से स्पष्ट किया है, निवेश, विशेषकर निजी निवेश “मुख्य प्रेरक” है जो मांग, क्षमता निर्माण, श्रम उत्पादकता में वृद्धि करता है, नई प्रौद्योगिकी आरंभ करता है, ध्वंस की अनुमति देता है और रोजगार का सृजन करता है।

1.16 परंपरागत मॉडल से सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि हम अर्थव्यवस्था को निरंतर असंतुलनग्रस्त मानते हैं, चाहे यह सद्चक्र हो या दुश्चक्र। जब अर्थव्यवस्था एक सद्चक्र में होती है तो निवेश उत्पादकता वृद्धि, रोजगार सृजन, मांग और निर्यात सभी में ऊर्जा का संचार होता है और सफलता पाने के लिए अर्थव्यवस्था संभावनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में सक्षम होती है। इसके विपरीत, जब अर्थव्यवस्था दुश्चक्र में होती है तो प्रत्येक क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति बनी रहती है और संभावनाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है।

1.17 जैसा कि अगले खंड में वर्णन किया गया है, हमारी अर्थव्यवस्था का नजरिया, एक गुणकारी चक्र—या दुश्चक्र होगा। इनमें निवेश ही मुख्य प्रचालक होगा। यह

अर्थव्यवस्था के पारंपरिक एंग्लो-सेक्सेन नजरिये से दो प्रकार से भिन्न है।

1.18 पहला, इस पारंपरिक नजरिये को जिसे वैश्विक वित्तीय मंदी से कई महत्वपूर्ण चुनौतियां मिली हैं, उसमें एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में संतुलन की संकल्पना विचारणीय होती है। इसके वितरीत, इंजीनियरिंग तथा प्राकृतिक विज्ञान जैसे अन्य क्षेत्रों से कुछ सीखकर आत्मसात् करके, सद् अथवा दुश्चक्र से पार पाकर, हम अर्थव्यवस्था को निरंतर असंतुलन में बने रहने के नजरिये से देखेंगे।

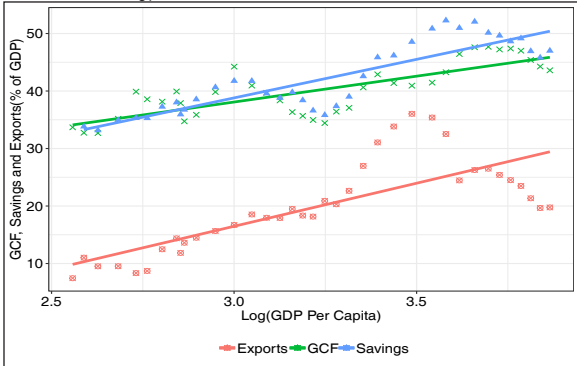
1.19 दूसरा, पारंपरिक दृष्टिकोण, रोजगार सृजन, मांग और निर्यात में वृद्धि, आर्थिक विकास की बहुविध समस्याओं को पृथक समस्या के रूप में मानकर उनके समाधान का प्रयास करता है। इसके विपरीत जैसा हमने नीचे दर्शाया है, ये समष्टि आर्थिक घटनाक्रम महत्वपूर्ण अनुपूरकता दिखाते हैं। अतः “प्रमुख प्रेरक” की समझ तथा अन्य सभी समष्टि घटनाचक्र वृद्धि को संभव बनाएंगे।

1.20 जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो समष्टि घटनाक्रम को शुरू करने वाला “प्रमुख प्रेरक” जो अर्थव्यवस्था को संकटपूर्ण स्थिति से उत्प्रेरित करके एक सद्चक्र में लाता है, निर्णायक बन जाता है। यह समीक्षा उस “प्रमुख प्रेरक” के रूप में निवेश की बात कर रही है जो एक स्वपोषित सद्चक्र तैयार कर सकता है। यह अवसरचना में सरकार का निवेश हो सकता है, जो निजी निवेश को भी आकर्षित करता है (चक्रवर्ती, सुब्रमणियन एवं अन्य, 2017)।

### “सद्चक्र” को समर्थन देते साक्ष्य

1.21 चित्र 2 दर्शाता है कि किसी तरह से जीसीएफ के अंश, बचत तथा निर्यात को जीडीपी में शामिल करना चीन के लिए 1980 से 2017 तक प्रति व्यक्ति जीडीपी को आगे बढ़ाने के कार्य के रूप में शामिल रहा है। आवश्यक रूप से हमने यह नोट भी किया है कि इन सभी तीन परिवर्तनीय समष्टि चक्रों का बढ़ जाना, देश के विकसित होने का द्योतक है इसीलिए चीन की बचत, निवेश तथा निर्यात में आगे और वृद्धिशील प्रति व्यक्ति जीडीपी के परिकलन में, अर्थव्यवस्था आरम्भ

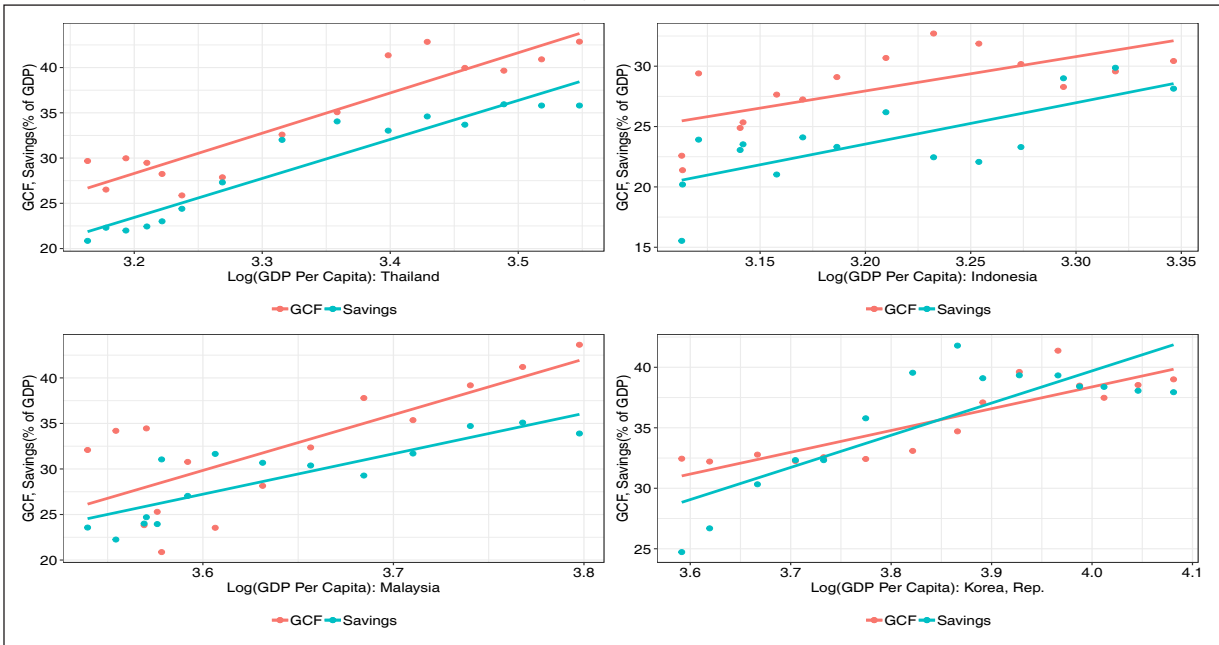
**चित्र 2: जीसीएफ, बचत तथा निर्यात की जीडीपी में हिस्सेदारी बनाम प्रति व्यक्ति जीडीपी निरंतर 2010 यूएस डॉलर: चीन (1980-2017)<sup>2</sup>**



स्रोत: विश्व बैंक

टिप्पणी: प्रति व्यक्ति जीडीपी स्थिर 2010 अमेरिकी डॉलर पर मापित है और उपयोग समय-अवधि 1980-2017 एक्स-एक्सिस हेतु लिया गया लघुगणक माप पठन को सरल बनाने के लिए आधार 10 के अनुसार है।

**चित्र 3: जीडीपी में जीएसएफ तथा बचत की हिस्सेदारी बनाम 2010 के स्थिर अमेरिकी डॉलर पर प्रति व्यक्ति जीडीपी: उच्च संवृद्धि वाली पूर्वी एशियन अर्थव्यवस्थाएं (1980-1995)**



आंकड़ा स्रोत: विश्व बैंक

टिप्पणी: प्रति व्यक्ति जीडीपी स्थिर 2010 अमेरिकी डॉलर पर मापित हुई है और इस्तेमाल समय-अवधि 1980-1995 है। एक्स-एक्सिस हेतु लिया गया लघुगणक माप पठन को सरल बनाने के लिए आधार 10 के अनुसार है। इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य तथा थाइलैंड की उच्च विकास वाली पूर्वी एशियन अर्थव्यवस्था।

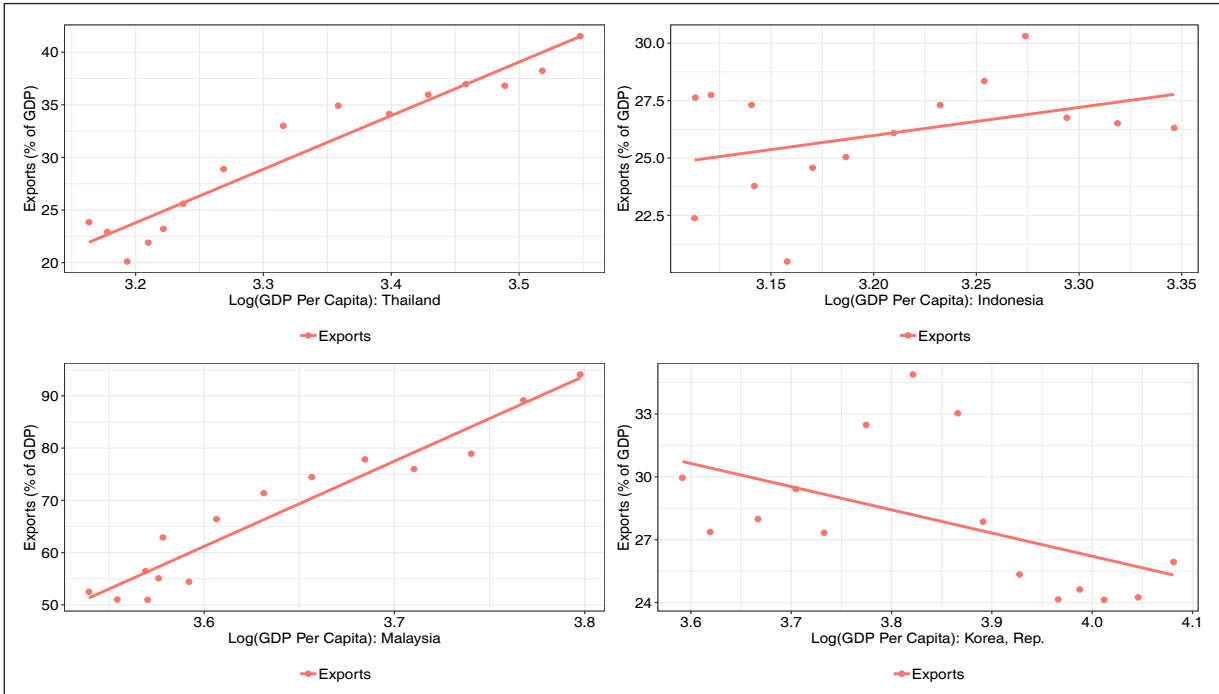
से ही अच्छी रही है<sup>3</sup>। चित्र 3 और 4 यह दर्शाता है कि पूर्वी एशिया (थाइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और कोरिया गणराज्य) में चारों देशों का बचत और निवेश से वही संबंध है, जो एशियन वित्तीय संकट से पहले उच्च संवृद्धि से इन क्षेत्रों में नियोजित समयावधि 1980-1995 है अर्थात् एशियन वित्तीय संकट से पहले की जबकि चित्र 3 निवेश और बचत का संबंध दर्शाता है। चित्र 4 दक्षिण कोरिया को छोड़कर बाकी के संबंध में निर्यात दर्शाता है। चित्र 3 तथा 4 की जांच करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि जो हमने चीन के आंकड़े देखे वे भी इसी के समान रहे हैं।

1.22 संद्री (2014) उसी घटना का एक भिन्न दृष्टिकोण प्रदान करता है। गैर-ओईसीडी देशों में 1960 से 2011 तक संवृद्धि उछाल की 62 घटनाओं का औसत निकालने पर, संद्री (2014) दर्शाता है कि इन घटनाक्रमों

<sup>2</sup> निवेश और प्रति व्यक्ति जीडीपी के लघु गणकों के बीच संबंध की जांच करने के स्थान पर, जो एक सद् चक्र को अंगीकार नहीं करेगी, हमें प्रति व्यक्ति जीडीपी की गति के लिए जीडीपी में निवेश की हिस्सेदारी के बीच संबंध की जांच करनी है ताकि प्रति व्यक्ति जीडीपी में किसी बदलाव के साथ इस हिस्सेदारी में बदलाव की जांच की जा सकती है। उसी तरह से वार्ड-अक्ष के संबंध में निर्यात में हिस्सेदारी के उपयोग तथा जीडीपी हेतु बचत के लिए यहीं तक लागू होता है।

<sup>3</sup> यद्यपि चीन के लिए जीडीपी निर्यात में अनुपात घातांकीय वृद्धि हुई है और उसके बाद, वर्ष, 2000 में कमी आई। समग्र रूप में रेखिक प्रवृत्ति अभी भी वृद्धिमान है।

**चित्र 4: जीडीपी में निर्यात (%) की हिस्सेदारी बनाम 2010 के स्थिर अमेरिकी डॉलर पर प्रति व्यक्ति जीडीपी: उच्च संवृद्धि वाली पूर्वी एशियन अर्थव्यवस्था (1980-1995)**



स्रोत: विश्व बैंक

टिप्पणी: प्रति व्यक्ति जीडीपी स्थिर 2010 के अमेरिकी डॉलर पर मापित है और इस्तेमाल समय-अवधि 1980-1995 है। एक्स-एक्सिस हेतु लिया गया लघुगणक माप पठन को सरल बनाने के लिए आधार 10 के अनुसार है। इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य तथा थाइलैंड की उच्च विकास पूर्वी एशियन अर्थव्यवस्था।

में उत्पादकता वृद्धि, तेजी से बढ़ रहे निवेश के साथ जुड़ी हुई है और यहां तक कि बचत दर भी तेजी से ऊपर जा रही है।

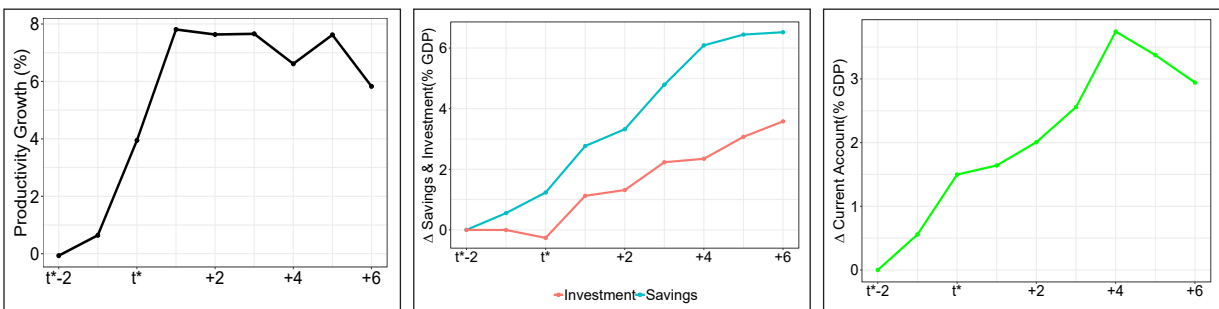
1.23 चीन ने जीडीपी के अंश के रूप में उपभोग में महत्वपूर्ण कमी करने के साथ मुख्य रूप से बचत तथा निवेश पर निर्भर किया है (चित्र 6)। चीन एक निवेशोन्मुखी अर्थव्यवस्था पर कायम है यहां तक आज भी इसकी निवेश तथा बचत दरें 2017 में जीडीपी के

लगभग 45 प्रतिशत तक पहुंच गई हैं।

1.24 चीन और अन्य पूर्वी एशियाई देशों में चित्र 7 सकल पूंजी निर्माण तथा जीडीपी एवं निवेश के बीच सशक्त सहसंबंध दर्शाता है। चित्र 8 ने इतना ही सशक्त संबंध निवेश और बचत में दर्शाया है।

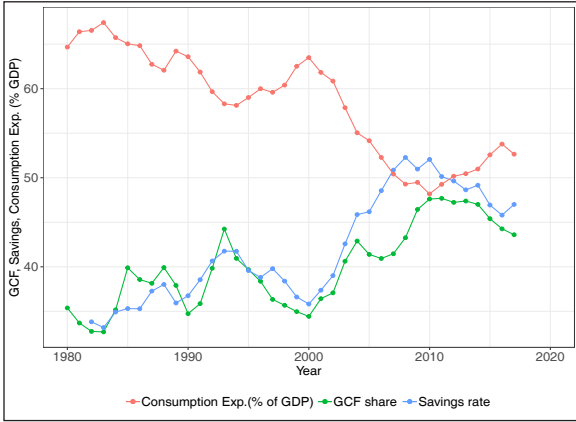
1.25 अतः इस खण्ड में साक्ष्य ये सुझाव देते हैं कि बचत, निवेश तथा जीडीपी विकास दर, उच्च विकास

**चित्र 5: गैर-ओईसीडी देशों में संवृद्धि उछाल की 62 घटनाओं से उत्पादकता, निवेश, बचत तथा चालू खाते में बदलाव (1960-2011)**



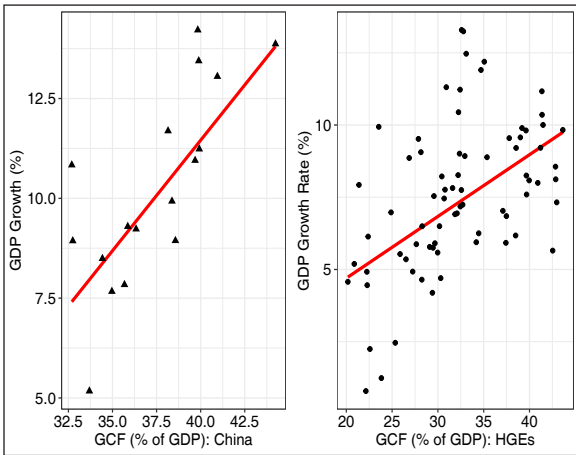
स्रोत: संडी (2014)

**चित्र 6: चीन में उपभोग, सकल पूंजी निर्माण और बचत के जीडीपी से अनुपात (1980-2017)**



स्रोत: विश्व बैंक

**चित्र 7: चीन तथा जीडीपी वृद्धि बनाम सकल पूंजी निर्माण और जीडीपी अनुपात: अर्थव्यवस्था से 1980-2000**



स्रोत: विश्व बैंक

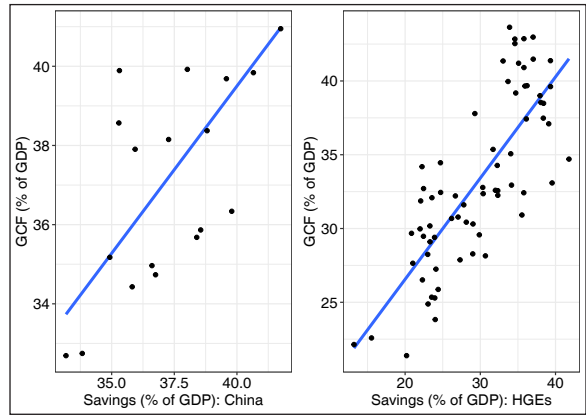
टिप्पणी: बायां पैनल चीन के लिए संबंध दर्शाता है, जबकि दायां पैनल थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया है तथा कोरिया गणराज्य की पूर्वी एशियन की चार उच्च संवृद्धिशील अर्थव्यवस्थाओं हेतु है। टिप्पणी: उपयोग की गई समयावधि 1980-2000 है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और कोरिया गणराज्य के चार उच्च विकास दर वाली पूर्वी एशियन अर्थव्यवस्थाएं एचजीई के लिए है।

वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक सद्चक्र ने विकास किया है जैसा चीन अथवा पूर्वी एशियन अर्थव्यवस्थाएं दर्शा रही हैं।

**बचत की महत्ता**

1.26 जैसाकि फैल्डस्टेन और होरिओका (1980) जिस

**चित्र 8: चीन तथा उच्च विकास दर वाली पूर्वी एशियन अर्थव्यवस्थाओं (1980-2000) में जीडीपी, सकल पूंजी निर्माण बनाम बचत दर**



आंकड़ा स्रोत: विश्व बैंक

टिप्पणी: बायां पैनल चीन के लिए संबंध दर्शाता है, जबकि दायां पैनल थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, तथा कोरिया गणराज्य की पूर्वी एशियन अर्थव्यवस्थाओं के लिए है। उपयोग की गई समयावधि 1980-2000 है।

पर “फैल्डस्टेन-होरिओका पजल” का लेबल लगा दिया गया है ने प्रदर्शित किया है, एक उच्च निवेश करने के प्रयास को घरेलू बचतों से समर्थन मिलना चाहिए। इसके आगे के अनुसंधानों (कैरोल तथा वील, 1994; अट्टानासियो, पिक्की तथा सोरकु, 2000; रोड्रिक, 2000) ने यह दर्शाया है कि बचत और संवृद्धि का न केवल आपसी सकारात्मक संबंध होता है बल्कि उनका सकारात्मक संबंध संवृद्धि तथा निवेश (गोरिचास तथा जीने, 2013) के संबंध से भी मजबूत है। तथ्य में संड्री (2014) का तर्क है कि निवेश जोखिमपूर्ण है, उद्यमियों ने विशेष स्वभाव में व्यापार के असफल होने के जोखिमों का खुलासा किया है जिससे निवेशित राशि में घाटा हो सकता है। अतः सावधानीपूर्वक बचत संचय की अनुमति के लिए निवेश के मुकाबले बचत को बढ़ाया जाना चाहिए। संवृद्धि में उछाल (चित्र 5) के 62 एपीसोडों के लिए संड्री (2014) से साक्ष्य और चीन (चित्र: 6) वही दर्शाते हैं।

**रोजगार**

1.27 एक सामान्य आशंका है कि उच्च निवेश दर श्रमिकों का प्रतिस्थापन करती है। इस धारणा ने पूंजी सघन और श्रम सघन उत्पादन तन्त्रों को लेकर एक

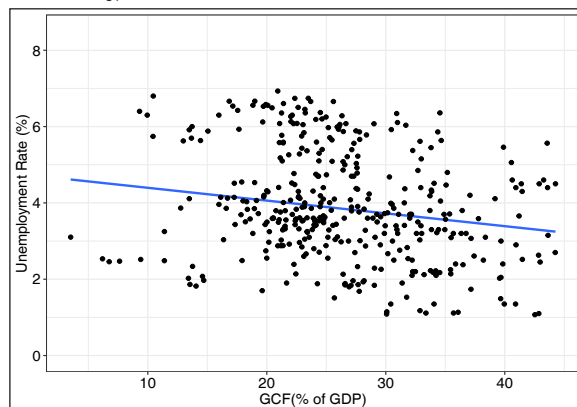


विवाद को जन्म दिया है किन्तु चीन का अनुभव तो उच्चतम निवेशदर के साथ रोजगार सृजन भी दिखा रहा है। महत्व इस बात का है कि क्या निवेश उत्पादित और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाशीलता को भी बढ़ाया जा रहा है। आशंकाएं पुरातन धारणाओं से ग्रस्त चिंतन का परिणाम हैं। जब पूर्ण मूल्य शृंखला की जांच करते हैं तो पूंजी निवेश रोजगार का पालक सिद्ध होता है क्योंकि पूंजीगत उत्पादन, शोध और विकास तथा आपूर्ति शृंखलाएं भी रोजगार सृजन करती हैं। चक्र के केन्द्रीय महत्व की कल्पना रही है जो सारी अर्थव्यवस्था में एक सद्चक्र को संप्रेरित कर सकता हो। समीक्षा निवेश को ऐसा निर्णायक चालक मानती है। आंकड़ों के सार्वजनिक पदार्थ का रूप देकर, विधिक सुधारों पर आग्रह करके, नीतियों में सुसंगति सुनिश्चित करके तथा व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के अनुरूप व्यवहार परिवर्तन को संप्रेरित अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्यों ने भी सुझाव दिया है कि पूंजी तथा श्रम पूरक होते हैं और उच्च निवेश दर संवृद्धि को प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए लिन (2011) दर्शाता है कि सॉफ्टवेयरों तथा कंप्यूटरों के आने से, कुछ सफेद कॉलर कार्य प्रतिस्थापित हुए हैं, सॉफ्टवेयर ओर एप्लीकेशन विकास, कंप्यूटर सुरक्षा तथा ऋण आवेदन, विश्लेषण तथा उपकरण तकनीशियन आदि के लिए विशेषज्ञ कार्य से संबंधित नए श्रम आधारित कार्य भी सृजित हुए हैं।<sup>4</sup> चित्र 9 पूर्वी एशिया पैसिफिक में अधिक सकल पूंजी होने से कैसे बेरोजगारी दरें घटती है, को दर्शाता है इससे यह भी पता चलता है कि श्रम और निवेश एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए रोजगार सृजन, वास्तव में निवेश को प्रोत्साहित करके किया जा सकता है।

## निर्यात

1.28 उच्च स्तरीय बचत द्वारा प्रतिबंधित उपभोग के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अंश प्रबल प्रवर्धक के रूप में कार्य कर सकता है जब उच्च आय वृद्धि उपभोग को पोषित करती हो, तो उच्च निवेश से संभव उत्पादन के लिए मार्ग कहां से आएगा? उत्तर है उच्च निर्यातों

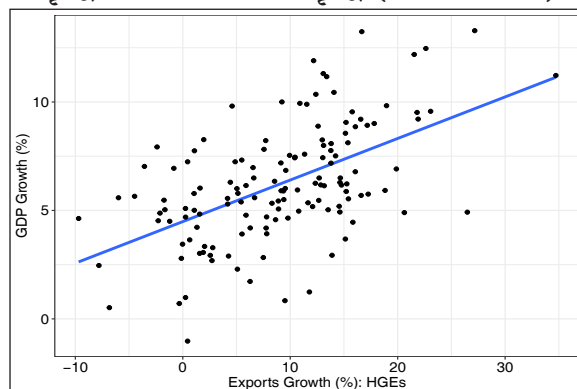
**चित्र 9: पूर्वी एशिया और पैसिफिक की बेरोजगारी दर बनाम सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) (1960-2017)**



डाटा स्रोत: विश्व बैंक

से। यही कारण है कि उद्यमशील निर्यात नीति किसी निवेश-संचालित विकास मॉडल का भाग होना चाहिए। चित्र 10 पूर्वी एशिया की उच्च वृद्धि अर्थव्यवस्थाओं के लिए निर्यातों में वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में घनिष्ठ सहसंबंध दर्शाता है।

**चित्र 10: उच्च वृद्धि वाली एशियन अर्थव्यवस्थाओं के लिए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि बनाम निर्यातों में वृद्धि (1960-2017)**



डाटा स्रोत: विश्व बैंक

टिप्पणी: ली गई समयावधि वर्ष 1980-2017 है तथा उच्च वृद्धि पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणतंत्र और थाईलैंड के संगत हैं।

<sup>4</sup> चीन में इसके प्रभावशाली विकास के इंजन बनाने वाले शहरी और ग्रामीण उद्यमों (टीवीई) की सफलता की कहानी यह दर्शाती है कि कैसे श्रम-प्रोत्साहन विनिवेश से उत्पादकता रोजगार सृजन एवं निर्यात को एक साथ बढ़ावा मिल सकता है (वी एवं बालासुब्रमण्यम 2015) जबकि वर्ष 1980 (टीवीई) में लगभग 1.4 मिलियन शहरी और ग्रामीण उद्यम थे जिसमें 30 मिलियन कर्मचारी थे, वर्ष 1996 तक 23.4 मिलियन शहरी एवं ग्रामीण उद्यम थे जिसमें 135 मिलियन कामगार थे जिनका योगदान चीन के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 30 प्रतिशत और औद्योगिक आउटपुट का 50 प्रतिशत था (पेरोटी और अन्य)। वर्ष 1999 तक शहरी एवं ग्रामीण उद्यम निर्यात का योगदान चीन के कुल निर्यातों का 48 प्रतिशत था इनमें से अधिकांश श्रम-प्रोत्साहन विनिवेश उत्पाद थे जिसमें साधारण उत्पादन तकनीकें थी (फू और बालासुब्रमण्यम, 2005)।

1.29 वैश्विक बाजार ऐसी फर्मों के साथ अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में है जो निर्यातों में बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करने की योग्यता के साथ निम्नतम लागतों पर उत्पादन करने में समर्थ होती हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था में फर्मों की औसत उत्पादकता निर्यात प्रतिस्पर्धा के मामले में महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसाकि चित्र 11 में देखा गया है, पूंजी निवेश कुल सकल कारक उत्पादकता का संवर्धन करता है जो बदले में निर्यात कार्य निष्पादन में वृद्धि करती है। इसलिए, निर्यात कार्यनिष्पादन में वृद्धि करने के लिए निवेश महत्वपूर्ण हो जाता है।

1.30 यद्यपि यह सत्य है कि विश्व-व्यापार वर्तमान में कुछ अड़चनों का सामना कर रहा है तथापि, वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा इतना कम है कि इसे बाजार हिस्सेदारी पर फोकस करने की अति आवश्यकता है। कोई यह तर्क भी दे सकता है कि वर्तमान अड़चनें भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में स्वयं को प्रविष्ट कराने का अवसर प्रदान करती हैं। डॉ. सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय सलाहकार समूह ने जून, 2019 में इस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भारत कैसे अपने निर्यातों को बढ़ा सकता है। इसकी सिफारिशों का अध्ययन किए जाने और यथा संभाव्यता कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता है।

### मूल योजना में “संतुलन” के अर्थशास्त्र से आगे जाना

“यदि मनुष्य को सामाजिक-सुधार प्रयासों में औचित्य से अधिक अहित नहीं करना हो तो उसे यह सीख मिलेगी

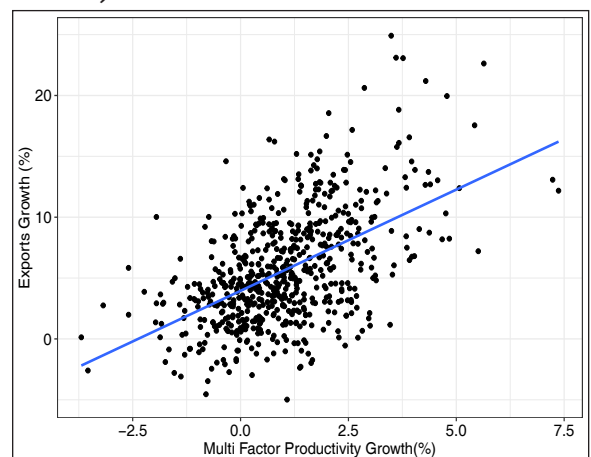
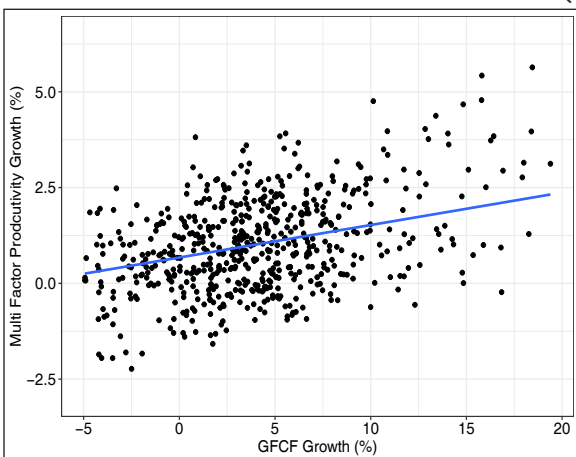
कि इसमें, जैसाकि ऐसे अन्य तमाम क्षेत्रों में होता है जिनमें एक संगठित प्रकार की अनिवार्य जटिलता की स्थिति विद्यमान होती है, वह उस पूर्ण ज्ञान का अर्जन नहीं कर सकता जो उसे घटनाओं का विशेषज्ञ बना सके। इसलिए उसे उसी ज्ञान का उपयोग करना होगा जो वह प्राप्त कर सकता है, परिणामों को वह स्वरूप प्रदान करने के लिए नहीं जो कोई शिल्पकार अपनी कलाकृति को आकार देने के लिए करता है, बल्कि एक ऐसी रीति से समुचित वातावरण प्रदान करते हुए विकास को आगे ले जाने के लिए, जैसे कोई माली अपने पौधों को बढ़ाने के लिए करता है।”

—फ्रेडरिक वॉन हायॅक, नोबेल पुरस्कार भाषण, 1974

1.31 जैसाकि हेक (1974) के उपर्युक्त उद्धरण से प्रदर्शित होता है, मूल योजना (ब्लूप्रिंट) का प्रारंभ इस दर्शन से होता है कि अर्थव्यवस्थाएं विस्तृत रूप में परस्पर गुंथी हुई प्रणालियां होती हैं। इसलिए, इन्हें न तो कोठरियों के रूप में सार्थक रूप में देखा जा सकता है और न ही समय के साथ गतिमान-प्रभावों का लेखा किए बिना इनका विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा, विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं बमुश्किल ही संतुलन की स्थिति में होती हैं। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद आर्थिक सिद्धांतों के बारे में लिखते समय, रोड्रिक (2018) का कथन है:

“हम पूरी तरह से विवेकपूर्ण व्यक्ति पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित क्यों करते हैं जबकि वास्तविक लोग उस तरह का व्यवहार करते दिखाई नहीं पड़ते? संतुलन के अतिरिक्त हमें असंतुलन पर थोड़ा अधिक ध्यान क्यों

चित्र 11: उत्पादकता पर तथा उसके बाद ओईसीडी देशों के लिए निर्यातों पर जीसीएफसी वृद्धि का प्रभाव ( 1985-2017 )



स्रोत: ओईसीडी डाटाबेस।

नहीं देना चाहिए? हमारे मॉडलों से उन सामाजिक एवं संस्थागत पहलुओं को बाहर क्यों रखा जाता है जिनके बिना बाजार कार्य नहीं कर सकते? क्यों हम आंकड़ों पर इतना अधिक जोर देते हैं और ऐसी चीजों की उपेक्षा करते हैं जिनकी आसानी से मात्रा तय न की जा सके?"

1.32 वैश्विक वित्तीय संकट के बाद आर्थिक मॉडलों में अपूर्णताओं को रेखांकित करने के लिए ओईसीडी ने 'न्यू एप्रोचेज टु इकॉनॉमिक चैलेंजेज' (एनएईसी) समूह का सृजन किया। एनएईसी पर लिखे एक ब्लॉग में, रामोस (2017) रेखांकित करते हैं:-

“इन मॉडलों (पारंपरिक आर्थिक) का नाम, सामान्य संतुलन ही दर्शाता है कि इनमें यह माना जाता है कि अर्थव्यवस्था मूलतः तभी तक संतुलन बनाए रखने की स्थिति में होती है जब तक कि कोई बाहरी आघात इसमें व्यवधान न कर दे। ये मानते हैं कि आप किसी ऐसे प्रतिनिधि अधिकर्ता के माध्यम से अर्थव्यवस्था की समझ प्राप्त कर सकते हैं जिसकी अपेक्षाओं और निर्णयों को तर्कसंगत मान लिया जाए। यह विचार आवश्यक तौर पर रैखिक है और इसके द्वारा निर्मित की जाने वाली नीतिगत सलाह का ताना-बाना एक रैखिक प्रणाली में बना जाता है जहां कोई भी क्रिया निष्पक्ष रूप से अनुमान योग्य प्रतिक्रिया को जन्म देती है.....वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता.....। हमें अर्थशास्त्र के

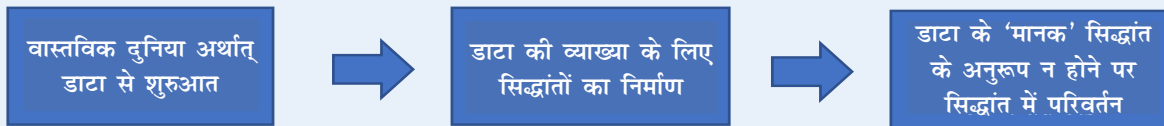
एक नए उपागम की जरूरत है जो केवल मात्रात्मक अर्थशास्त्र के विषय में न हो। वह एक ऐसा उपागम हो जो व्यवहारवादी अर्थशास्त्र और जटिल प्रणालीगत सिद्धांतों तथा साथ-ही-साथ आर्थिक इतिहास, सभी को एकीकृत रूप में आत्मसात करे।”

1.33 जैसाकि बॉक्स 1 में दर्शाया गया है, वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट ने इस बात को रेखांकित किया कि अर्थव्यवस्था एक ऐसे दुश्चक्र के फंसी हो सकती है जहां मांग, नौकरियों और निवेश में शिथिलता एक दूसरे को प्रभावित करती है और अर्थव्यवस्था में उत्साह की स्थिति को समाप्त करती है। इसलिए, जैसाकि रोककर(2015), रामोस (2017) और रोड्रिक (2018) द्वारा रेखांकित किया गया है, आर्थिक विचारक अब स्वीकार करते हैं कि अर्थशास्त्र में अन्य क्षेत्रों से ली गई सीख को आत्मसात किया जाना जरूरी है। इनका मानना है कि किसी अर्थव्यवस्था के विषय में यह विचार रखना कि वह सदैव संतुलन की स्थिति में रहती है, एक निरंतर परिवर्तनशील दुनिया में “मानक” फ्रेमवर्क को बलात् टूटने जैसा होगा। इसकी बजाय अर्थव्यवस्थाओं के बारे में यह विचार कि वे सद्चक्रों या दुश्चक्रों में निरंतर असंतुलन में बनी रहती है, मौजूदा समय में एक अधिक उपयुक्त फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है।

### बॉक्स 1: भारत के संदर्भ में आर्थिक सिद्धांत के पुनः विन्यास की जरूरत

वैश्विक वित्तीय संकट ने पारंपरिक समष्टि अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों में व्याप्त समस्याओं को उजागर किया (सुब्रमण्यम, 2011)। तो भी, इस विफलता को, आर्थिक चिंतन को विघटित करने के बहाने के रूप में प्रयोग करना “गंठू के साथ घुन को पीसने” जैसा होगा क्योंकि हमारे क्षेत्र में हमारे चिंतन को अनुशासित करने के लिए तथा सतर्क नीति-निर्माण में समर्थ बनाने के लिए सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। इसलिए सामान्य तौर पर आर्थिक सिद्धांतों और विशेष तौर पर समष्टि अर्थशास्त्र को एक ऐसी दुनिया के अनुकूल बनाना आवश्यक हो सकता है जो निरंतर असंतुलन की स्थिति में है। इस संदर्भ में, अर्थशास्त्र में सिद्धांत-निर्माण की प्रक्रिया तथा इसके विपर्यय में अन्य विषयों की तत्संबंधी प्रक्रिया को समझना उपयोगी है ताकि हम भारत में आर्थिक संवृद्धि का समुचित मॉडल विकसित कर सकें।

अर्थशास्त्र में सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार चलती है:

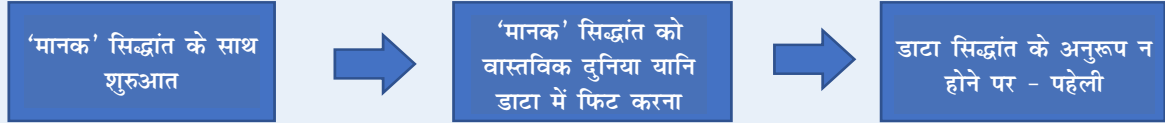


अर्थशास्त्र में सिद्धांत-निर्माण प्रक्रिया में त्रुटि को समझने के लिए लूकास (1990) के क्लासिक पेपर पर विचार करें। इस अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि पूंजी का प्रवाह मानक सिद्धांत के अनुसार पूंजी-बहुल देशों से पूंजी-न्यून देशों की ओर क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि परवर्ती से अधिक लाभ प्राप्त होंगे। इस वाक्यांश में ही अंतर्निहित दोष छिपा है कि “जैसा मानक सिद्धांत में पूर्वानुमानित है।” यह सिद्धांत कुछ ऐसी पूर्वधारणाओं के साथ शुरू होता है जो “मानक” सिद्धांत को मानती हैं

जैसेकि, सदैव युक्तिसंगत निर्णय लेने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों के एक समूह की प्राथमिकताओं को “प्रतिनिधि अभिकर्ताओं/एजेंट” की ग्राह्यता के अनुसार कैप्चर किया जा सकता है, हासमान प्रतिफल नियम इत्यादि।

“मानक” सिद्धांत निर्माण करते हुए अध्ययन से ज्ञात हुआ कि यह सिद्धांत वास्तविक जगत कि अनुरूप नहीं है क्योंकि वास्तविक दुनिया में पूंजी का प्रवाह, निर्धन देशों से धनी देशों की ओर होता है न कि अमीर देशों से गरीब देशों की ओर। चीन से अमेरिका की ओर पूंजी का प्रवाह, एक प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता है हालांकि यह घटना अधिक व्यापक है। चूंकि “मानक” सिद्धांत, वास्तविक विश्व में फिट नहीं होता, इसलिए वास्तविक घटना क्रम को “एक पहेली” बता दिया जाता है। यह नहीं स्वीकार किया जाता कि यह सिद्धांत वास्तविक जगत की घटनाओं को प्रतिपादित करने के लिए अपर्याप्त है।

इसके विपरीत, अन्य विषयों, विशेष रूप से प्राकृतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी में सिद्धांत-निर्माण की प्रक्रिया निम्नलिखित रूप में आगे बढ़ती है:



यदि हम इस अनुशासन को अपनाते हैं तो इस परिघटना, लूकास का अध्ययन (1990), को किसी भी तरह से एक समस्या के रूप में नहीं देखा जा सकता। एक ऐसे व्यापार पर विचार करें जो अत्यंत उत्पादक हो तथा बहुत ही कम दरों पर सामान/माल का उत्पादन करने में सक्षम है जिससे बड़े मार्केट शेयर पर कब्जा हो सके तथा भारी मुनाफा कमाया जा सके। आमतौर पर अर्जित लाभ को अग्रिम निवेश के निधियन के लिए व्यापार में ही लगाया जाता है। परंतु मान लिया जाए कि लाभ इतना अधिक हो जाता है कि नई परियोजनाओं के निधिकरण के लिए आवश्यक समग्र राशि के पुनः निवेश/पुनर्निवेश के पश्चात् भी व्यापार में अधिक नकदी बच जाती है। अब कारोबारी इसका क्या करेगा? इस अतिरिक्त अधिक धनराशि को “अन्य परिसंपत्तियों” में निवेश करेगा। उदाहरण के लिए, कारोबारी अन्य प्रतिष्ठानों/फर्मों में निवेश कर सकता है। यही चीन कर रहा है। तब यह एक अनबूझ पहेली क्यों बनी हुई है?

मानक सिद्धांत का एक अन्य प्रमुख उदाहरण समष्टि अर्थशास्त्र में “गतिशील यादृच्छिक सामान्य संतुलन प्रतिमान [डायनेमिक स्टोचैस्टिक जनरल ईक्वीलिब्रियम मॉडल (डी.एस.जी.ई.)] का उपयोग है। इस क्षेत्र में व्यापक साहित्य उपलब्ध होने के बावजूद जिसमें कई डी.एस.जी.ई. आंकड़ों को माना गया है, संकटपूर्व मॉडल में वित्तीय क्षेत्र को ‘साईडशो’ ही माना गया है। इसीलिए डी.जी.एस.ई. मॉडल में वित्तीय क्षेत्र के भीतर संभावित त्रुटिपूर्ण आवंटन से उत्पन्न समस्याओं का जिक्र नहीं किया गया था। यह भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से प्रासंगिक है जिसने बैंकिंग क्षेत्र में संकट और अर्थव्यवस्था पर पैदा होने वाले ओवरहैंग के अनुभव को दिया है।

यद्यपि विकासमान साहित्य में डी.जी.एस.ई. मॉडलों की समस्या को सीमित किया है लेकिन यह परवर्ती फिक्सिंग उचित नहीं हो सकती क्योंकि कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटक जो वर्तमान मॉडलों से छूट गए हैं, को नए संकट को उजागर करने हेतु प्रतीक्षा करनी होगी। यह पूर्वाग्रह ही मानक सिद्धांतों के माध्यम से विश्व घटनाचक्र को समझ पाने में बाधक है। भारतीय संदर्भ में डीजीएसई प्रतिमान का प्रयोग नितान्त आवश्यक है क्योंकि भारत एंग्लो-सेक्सन देशों से बहुत ही भिन्न है।

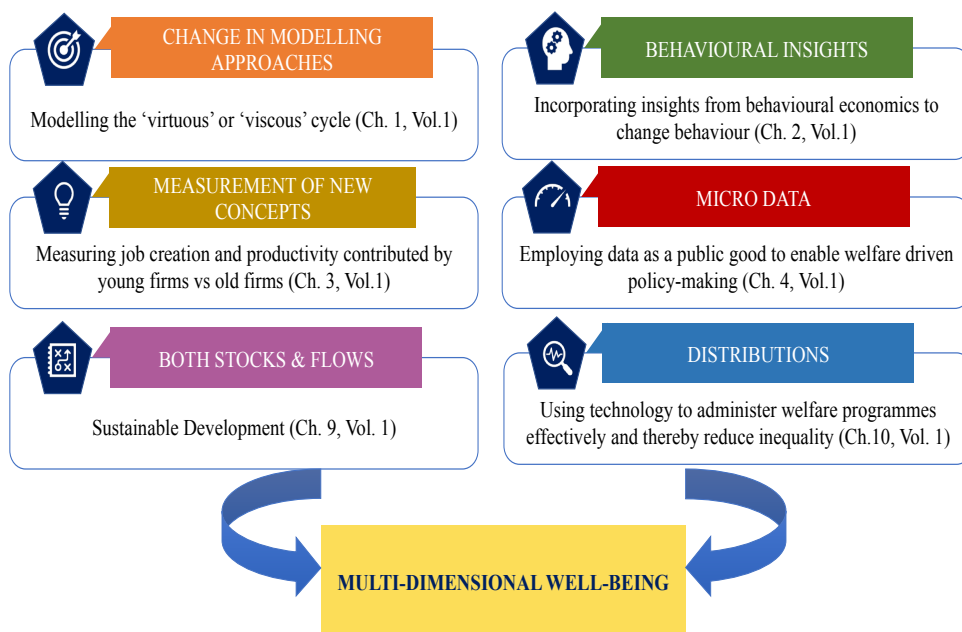
लूकास (1990) तथा डीजीएस ई प्रतिमानों पर अत्यधिक निर्भरता वही दो उदाहरण हैं जो भारत जैसे देशों की संस्थागत रूप से एंग्लो-सेक्सन अर्थव्यवस्थाओं से भिन्नता को समाहित करने के लिए समष्टि आर्थिक चिन्तन को और आगे विकसित करने की आवश्यकता की ओर इंगित करते हैं।

## निरंतर अस्थिरता में आगे बढ़ना

1.34 निरंतर अस्थिर अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए नए साधनों की आवश्यकता होती है। संतुलन के परिवेश को आधार बनाकर पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के प्रयास इसीलिए विफल रहे कि वे एक अन-नुमानिय विश्व में बहुत बड़े निश्चित उपाय बता रहे थे। ऐसे अस्थिर विश्व में आगे बढ़ने के लिए तीन तत्वों की आवश्यकता है: (प) स्पष्ट दृष्टि, चित्र, (पप) उस

दृष्टि चित्र को पाने के लिए एक सामान्य रणनीति और (पपप) नम्यता तथा अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने प्रयासों को पुनः विन्यासित करने की तत्परता पिछले अनुच्छेदों में हमने पांच ट्रिलियन अमेरिकी डालर की अर्थव्यवस्था बनने की एक दृष्टि चित्र रचा है। आइए अब उसके लिए तरकीबों पर ध्यान दें। चित्र-12 में नीचे दिया गया चित्र एनईएसी, ओईसीडी द्वारा सुझाव गए दृष्टिकोण को दर्शाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न

चित्र 12: निरंतर अस्थिर अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के साधन



स्रोत: एनईएसी, ओईसीडी।

तत्वों को एक साथ एकीकृत तरीके से तैयार करने की आवश्यकता के अलावा इस दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रूप से कई अन्य साधनों की आवश्यकता है। समीक्षा के खंड I के कई अध्यायों में इस दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने से संबंधित नीतिगत विवरण का खाका प्रस्तुत किया गया है। यह अध्याय विभिन्न आर्थिक घटनाक्रमों के समन्वित प्रतिमान की रूपरेखा बना रहा है। अध्याय-2 व्यवहार अर्थशास्त्र की संकल्पनाओं को गहराई से देखने अपनाने की चर्चा कर रहा है ताकि उत्पादिता और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिल सके। अध्याय-3 पुरानी और नई फर्मों की रोजगार और उत्पादिता वृद्धि के मापन के लिए नई संकल्पनाएं प्रतिपादित कर रहा है। अध्याय 10 दर्शा रहा है कि भारतीय समाज में बेहतर वितरणात्मक परिणाम पाने और कल्याण प्रभावों को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग लाभदायक हो सकता है। अध्याय-4 डेटा के सार्वजनिक पदार्थ स्वरूप से कल्याण वृद्धि की व्याख्या कर रहा है। अध्याय 9 में भारतीय अर्थव्यवस्था के संधारणीय विकास में ऊर्जा के प्रयोग पर ध्यान केन्द्रित कराया है।

### व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र

1.35 चूँकि नीति निर्माता को अनुकूलन केन्द्रित रोबोटों के बजाय, जैसा कि परम्परागत अर्थशास्त्र में परिकल्पना

की जाती थी, आम व्यक्ति पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, इसलिए व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र से प्राप्त अंतर्दृष्टियों को नीति निर्माण में एकीकृत किया जाना आवश्यक होता है ताकि उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि को उन्नत किया जा सके। इसलिए, समीक्षा के अध्याय 2 में इस विषय में गहराई से खोज की गई है। स्वच्छ भारत मिशन और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियानों द्वारा प्रभावित सफल व्यवहारात्मक परिवर्तन का विश्लेषण करके, इस अध्याय में उनकी शिक्षा शामिल की गई है और इस अध्याय में व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र को नीति तैयार करने में विविध संदर्भों में एकीकृत करने के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित किए गए हैं:

- (i) बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से शिशु लिंग अनुपातों को सुधारने में, विशेषकर उन बड़े राज्यों में, जिनमें शिशु लिंग अनुपात खराब था, मदद मिली है। इसलिए, इस अभियान का अधिकतम प्रभाव उन राज्यों में पड़ा था जिन्हें युक्तियुक्त रूप में भी अपने सामाजिक मानदंडों पर निर्भर रहने की आवश्यकता थी। इस अभियान से शिक्षा लेकर, इस अध्याय में 'बदलाव' (बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजय लक्ष्मी) स्लोगन तैयार करके लिंग समानता के मुद्दे को प्रोत्साहन

देने का प्रयास किया गया है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ कार्यबल और अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के योगदान में वृद्धि की जा सके।

- (ii) स्वच्छ भारत-मिशन से ऐसे गांवों के प्रतिशत में वृद्धि करने में मदद मिली है जो खुले में शौच जाने से मुक्त हैं और शौचालयों की सुलभता तथा उपयोग में वृद्धि हुई है। स्वच्छता में इस सुधार से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में मदद मिली है जैसा कि मलेरिया और डायरिया मामलों की संख्या से और मृत प्रसव तथा कम वजन के जन्मे बच्चों की संख्या से देखा जाता है। इस सफल व्यवहारात्मक परिवर्तन से प्राप्त शिक्षा को शामिल करके, इस अध्याय में स्वस्थ भारत के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन को सुन्दर भारत में परिवर्तित करने के विचार में यथा सन्निहित सुदृढ़ भारत के लिए व्यवहारात्मक अंतर्दृष्टियों के प्रयोग के लिए ढांचा तैयार किया गया है। यह रूपरेखा स्वस्थ भारत मिशन को स्वस्थ + आयुष्मान = सुन्दर भारत में परिवर्तित करना चाहती है। इससे श्रम उत्पादिता में वृद्धि होगी, बचतें बढ़ेगी और परिणाम स्वरूप निवेश थी।
- (iii) इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी (आईबीसी) प्रक्रिया के निर्माण ने बड़ी संख्या में अनर्जक परिसंपत्तियों को आईबीसी प्रक्रिया में लाने में सहायता की है। इसके अलावा, आईबीसी के तहत नियंत्रण खोने का खतरा देश में क्रेडिट संस्कृति को बदलने में सहायता कर रही है। “धार्मिक दायित्व के सिद्धांत” को अंकित करके व्यवहारिक अर्थशास्त्र की अंतर्दृष्टि का उपयोग, विशेष रूप से धोखाधड़ी और आदतन चूक के संबंध में क्रेडिट संस्कृति, को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
- (iv) कर प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से लाए गए कई परिवर्तनों ने कर प्रशासन में मानवीय हस्तक्षेप को कम कर दिया है और इससे बहुसंख्यक करदाताओं के अनुभव में सुधार हुआ है। कर संस्कृति को, कर अपवंचन से कर अनुपालन में बदलने के लिए व्यवहार संस्कृति का लाभ लिया जा सकता है। इसके बाद, इससे सड़कों, बंदरगाहों, रेलवे, आदि के ठोस अवसंरचनाओं और

कौशल एवं शिक्षा के मृदु अवसंरचनाओं दोनों में निवेश के लिए आवश्यक राजस्व की प्राप्त होगी।

- (v) जीएसटी, जहां नीति निर्धारकों ने हानि विरति को समाप्त करके एक बड़ा सुधार करने की अपनी क्षुधा को प्रदर्शित किया था, के उदाहरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक ऐसी नीति जिससे दीर्घकालीन लाभ के लिए कुछ अल्पकालीन नुकसान हो, उसे पर्याप्त समर्थन प्राप्त नहीं होता है (मिल्क मैन एवं अन्य 2012)। व्यवहार अंतर्दृष्टि हानि विमुखता को कम करने के लिए इस तरह के नवीन नीति परिवर्तन को अभिनीत करने के सकारात्मक परिणाम का निर्माण कर सकती है और इस तरह से नीति और विधायी परिणामों में सुधार हो सकता है।

1.36 नीचे दिया गया चित्र-13 व्यवहार अर्थशास्त्र के सात सिद्धांतों का सारांश प्रस्तुत करता है, जिनका उपयोग उपरोक्त परिणामों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। समीक्षा का अध्याय-2 इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में इसके उपयोग को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

### सार्वजनिक पदार्थ के रूप में डाटा

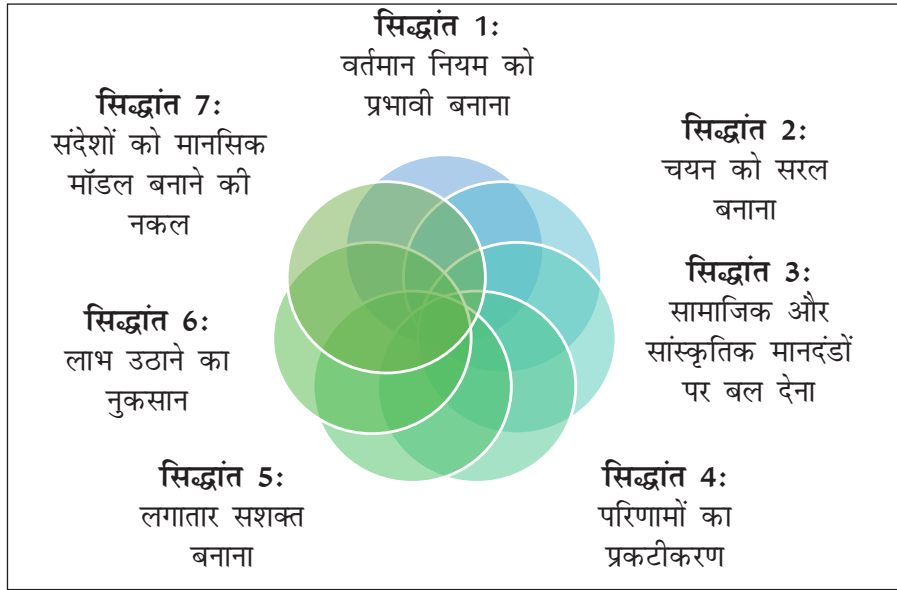
नदी पार करते समय उसके पत्थरों का ध्यान रखें।

—डेंग क्विसआओपिंग

1.37 पांच ट्रिलियन अमेरिकी डालर को अर्थव्यवस्था बनने की वृहत्त रणनीति की रूपरेखा बनाने के बाद भी इस लक्ष्य के लिए नीतियों में बार-बार सुधार करना आवश्यक होगा। यह आवश्यकता आंकड़ों पर आधारित साक्ष्य सुझा रहे हैं। डेंग क्विसआओपिंग द्वारा नदी पार करते समय पत्थरों को ध्यान रखने निकलने का आग्रह बहुत सार्थक प्रतीत होता है। यदि निरंतर असंतुलनशील अर्थव्यवस्था एक बहती हुई नदी है तो आंकड़ों पर आधारित नीति निर्माण आवश्यक पुनः विन्यास हेतु पत्थरों को ध्यान रखकर आगे बढ़ने जैसा है।

1.38 समीक्षा के खंड-1 का अध्याय-4 लोगों के, लोगों द्वारा और लोगों के लिए डेटा के निर्माण की रूपरेखा दे रहा है। अध्याय का विचार है कि समाज का अभीष्ट आंकड़ों का उपयोग पुराने समय से बहुत अधिक हो

चित्र 13: व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए व्यवहार अर्थशास्त्र के सिद्धांत



चला है। इसका एक कारण आंकड़ों की सीमांत लागत में घातांकीय कमी और समाज हेतु इसके सीमांत लाभ में बहुगुणित वृद्धि है। निजी क्षेत्र जहां लाभप्रद हो आंकड़े प्रयोग करने को तैयार रहता है किन्तु जहां इस आंकड़े निर्माण कार्य में निजी निवेश कम रह जाते हैं वहां सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। सरकार के पास पहले के ही प्रशासकीय, सर्वेक्षणजनित, संस्थागत तथा नागरिकों द्वारा लेन देन से सृजित आंकड़ों के विपुल भंडार हैं किन्तु ये विभिन्न सरकारी संगठनों में बिखरे हुए हैं। इन आंकड़ा भण्डारों का प्रयोग सरकार को जनता का जीवन सुगम बनाने, साक्ष्य आधारित नीतियां बनाने, कल्याणकारी नीतियों की लक्षिता सुधारने, अपूर्ण मांग पूरा करने, बिखरे हुए बाजारों को समेकित करने, सार्वजनिक सेवाओं में बेहतर उत्तरदेयता लाने, प्रशासन में जनभागीदारी सुधारने आदि में सहायता देगा। निजता की रक्षा की परिष्कृत प्रौद्योगिकी पहले से ही विद्यमान है अतः सरकार निजता की विधिक रूपरेखा में रहते हुए आंकड़ों को सार्वजनिक पदार्थ का रूप प्रदान कर सकती है।

### विधिक प्रणालियां और संविदा कार्यान्वयन

1.39 आद्यरूप में वर्णित आर्थिक मॉडल में परिवर्तनशील जटिल परिदृश्य में सद्चक्र के सृजन को स्पष्टतया बताया गया है। इस मॉडल में ऐसे वातावरण का उल्लेख किया गया है जहां निवेश, जोखिम का

उठाया जाना और नवीनताएं हैं और जहां परिवर्तनशील प्रौद्योगिकी, उपभोक्ताओं के भू-राजनीति में अभिरुचि तथा आर्थिक चक्रों जैसे कारकों के कारण “अनिश्चितता” तथा “अपूर्वानुमेयता” अंतर्निहित बन गई है। इस विश्व में “बटरफ्लाई” (जहां एक छोटा सा परिवर्तन बड़े परिवर्तनों का कारण बन जाता है)” और “अनजाने परिणामों” को देखा जा सकता है जहां अनिश्चितता अपरिहार्य रूप से विद्यमान है जैसाकि ‘अनिश्चितता’ प्रलोभनों को तीव्र कर सकती है, जिसके कारण संविदा भंग हो जाती है, ऐसा तब होता है जब कार्योत्तर निर्गम उस से भिन्न हो जाता है जैसाकि पूर्वानुमान किया गया होता है, तो ऐसे अनिश्चित विश्व में मार्गदर्शन के लिए “संविदाओं को कार्यान्वित करने की क्षमता तथा “विधि सम्मत शासन “The Rule of Law” ” महत्वपूर्ण बन जाते हैं। (आचार्य और सुब्रमनियन, 2009; आर्चाय, बध ई और सुब्रामनियन, 2013 2014; चावा और अन्य, 2013; सप्रा, सुब्रामनियन और सुब्रामनयन, 2013; सुब्रामनियन और तुग, 2016 सुब्रामनियन और मैगिनसन, 2018)। हालांकि एक सुचारू रूप से कार्य करने वाली विधिक प्रणाली सभी पारिस्थितियों में अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होती है किन्तु अपूर्वानुमेय विश्व में यह ‘पूर्णतया मुख्यार्थ’ हो जाती है क्योंकि यहां उच्च निवेश दरों के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा होता है।

1.40 चाणक्य तथा कर्मादक जैसे भारतीय विचारकों ने

विधिक प्रणाली और संविदा कार्यान्वयन के महत्व पर बार-बार बल दिया है। इन्होंने “विधि सम्मत शासन” को मत्स्य-न्याय (जंगल राज) से बचाने वाला बताया है। नोबल पुरस्कार विजेता आस्ट्रिया के अर्थ-शास्त्री “फ्रेडरिच वॉन हेक” ने इसी तथ्य को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “द रोड टू सर्फडॅम” में बताया है कि “सरकार अपने सभी कार्यों में पहले से घोषित तथा नियत किए जा चुके नियमों से बंधी है”।

*एक स्वतंत्र देश में कोई भी अधिक स्पष्ट परिस्थिति निरंकुश शासन के अंतर्गत देश में उनकी परिस्थितियों से विधि सम्मत शासन के रूप में जाने वाले महान सिद्धांतों के पूर्व में अवलोकन की अपेक्षा अधिक पहचाना नहीं गया।*

1.41 दुर्भाग्य से, भारत की कानूनी पद्धति, जिस पर 3.5 करोड़ लंबित मामलों का बोझ है, विवादास्पद रूप से अब भारत में व्यापार करने की एकमात्र सबसे बड़ी बाधा है और इस बाधा के कारण निवेश को बढ़ाया नहीं जा सकता। विश्व बैंक की व्यापार करने की सुगमता संबंधी नवीनतम रिपोर्ट में संविदा प्रवर्तन के लिए भारत 163वें स्थान पर है। अनुभव से पता चलता है कि आर्थिक सुधार-संपत्ति अधिकारों, करों एवं ऋण शोधन सुधार-संपत्ति अधिकारों, करों एवं ऋण शोधन अक्षमता के प्रत्येक अन्य क्षेत्र में समय-समय पर लड़खड़ाहट आती है क्योंकि यह कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाता है। यही कारण है कि कानूनी क्षेत्र सुधारों को शीर्ष प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

1.42 अच्छी खबर यह है कि समस्या जटिल नहीं है। अध्याय 5 में हमने देखा है कि निचली अदालतों में मात्र 2279 अतिरिक्त न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों में और 93 जजों की सहायता से पांच वर्षों में ही 100 प्रतिशत मामले निपटाने की दर (अर्थात् शून्य संचय दर) प्राप्त की जा सकती है। यहां यह भी सुझाया जा रहा है कि दक्षता में महत्वपूर्ण वृद्धि संभव है। वर्तमान संस्वीकृत पद संख्या पर निम्न, उच्च तथा सर्वोच्च न्यायालयों में क्रमशः 24.5 प्रतिशत, 4.3 प्रतिशत और 18 प्रतिशत उत्पादिता वृद्धि की आवश्यकता होगी। प्रौद्योगिकी का प्रयोग, कार्य दिवस संख्या में वृद्धि तथा प्रशासकीय सुधार इन महत्वाकांक्षी उत्पादिता वृद्धि लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। एक सुचारू न्यायव्यवस्था के सामाजिक गुणक स्वरूपी प्रभावों को देखते हुए कानून व्यवस्था को सुदृढ़

करना वह सर्वोत्तम निवेश होगा जिसे भारत के सुधारक कर सकते हैं।

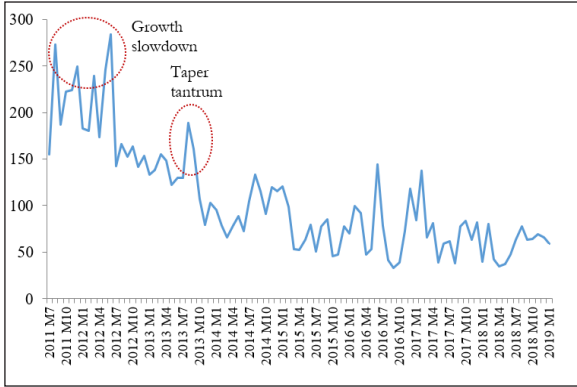
### आर्थिक नीति निर्धारण में संगतता

1.43 निरंतर अनिश्चितता की दुनिया में, आर्थिक नीति निर्धारण या तो निवेशकों के सामने आने वाली अनिश्चितता को कम करता है या उसको बढ़ा देता है। इस समस्या के समाधान के लिए लक्षित पंच वर्षीय योजनाओं के सृजन का पहले प्रयास किया गया था। हालांकि, जैसे ही हमें इस आर्थिक अस्थिरता का पता चला तो उक्त आर्थिक अस्थिरता के समाधान स्वरूप बेहतर योजनाएं बनायी गईं। अतः इस अस्थिर आर्थिक जगत में आगे बढ़ने के लिए तीन तत्वों की जरूरत होगी—(i) स्पष्ट विजन; (ii) विजन को हासिल करने के लिए सामान्य रणनीति; और (iii) अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करने के लिए रणनीतियों में लचीलेपन और उद्यम का समावेश हो सके। चूंकि प्रधानमंत्री का 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर वाली अर्थव्यवस्था के संबंध में अपना एक दृष्टिकोण है, अतः इस आर्थिक सर्वे के माध्यम से रणनीति के संबंध में एक ब्लूप्रिंट बनाकर इस विजन को प्राप्त करने का खाका तैयार किया जाता है। हालांकि यथा उपर्युक्त परिचर्चा के अनुसार, नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए वो रियल टाइम डाटा के प्रवाह के अनुरूप सतत रूप से प्रासंगिक हों।

1.44 इस तरह के सामरिक लचीलेपन से एक अन्य तरह की समस्या पैदा होती है जिसमें अनिश्चितता का माहौल बन जाता है। यह विशेष रूप से उन मामलों में होता है जब प्रमुख सुधारवादी कदम उठाए जा रहे हों। इस संदर्भ में समीक्षा के खंड I के अध्याय 6 में हमने पाया कि कैसे भारत में विगत कुछ वर्षों से आर्थिक अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सद्चक्र के प्रमुख कारक के रूप में निवेश पर बल देते हुए हमने निवेश के साथ आर्थिक नीति की अनिश्चितता के संबंध में जांच की है। हन आर्थिक नीति संबंधी अनिश्चितता का पता लगाने के लिए बेकर और अन्य (2016) सूचकांक का उपयोग करते हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण विश्व में आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता का पता लगाने के लिए बेकर एवं अन्य (2016) का उपयोग किया जाता है। हमने यह भी देखा है कि इस प्रकार की अनिश्चितता-अनिश्चितता के प्रकरण के दौरान अधिक थी जैसे वर्ष 2013 में



**चित्र 14: भारत में आर्थिक नीति अनिश्चितता (2011-2019)**



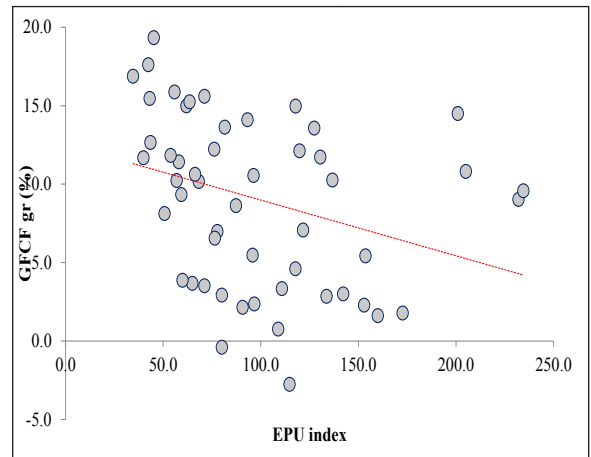
स्रोत: <http://www.policyuncertainty.com/>

टेपर टैट्रम, विमुद्रीकरण और जीएसटी का कार्यान्वयन। इस प्रकार समग्र आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता पिछले दशक में काफी अधिक थी (चित्र 14) इस आंकड़े की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि जीएसटी के लागू के साथ ही अत्यधिक बदलाव हुए, इसके बावजूद भी शायद ही आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता में वृद्धि हुई हो। इससे यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में जो अग्रणी सुधार हुए, वो सुनियोजित विजन के अनुरूप हैं और उक्त सुधार से अर्थव्यवस्था को उतने झटके नहीं लगे जितना कि कुछ लोग डर रहे थे। वर्ष 2015 के बाद भारत में आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता में लगातार गिरावट अपवाद स्वरूप है क्योंकि इस अवधि के दौरान प्रमुख देशों अमेरिका में आर्थिक नीतिगत अनिश्चितता में वृद्धि अत्यधिक प्रतिकूल थी।

1.45 आर्थिक नीति अनिश्चितता में उछाल से व्यवस्थित जोखिम में वृद्धि होती है, और उसके द्वारा अर्थव्यवस्था में पूंजी की लागत में वृद्धि होती है। परिणामतः आर्थिक नीति अनिश्चितता से निवेश में विशेष रूप से निवेश की अनवर्त्य के कारण कमी आती है। इस अभिधारणा के संगत, हम यह पाते हैं कि आर्थिक नीति अनिश्चितता में वृद्धि से भारत में निवेश वृद्धि में अवमंदन होता है (चित्र 15)। आवेश प्रतिक्रिया कार्य से यह सुझाव प्राप्त होता है कि आर्थिक नीति अनिश्चितता में वृद्धि से निवेश में वृद्धि लगभग पांच तिमाहियों तक प्रभावित होती है।

1.46 आर्थिक नीति की अनिश्चितता के प्रभाव से लगातार असंतुलन की स्थिति में अर्थव्यवस्था का प्रबंध करने में महत्वपूर्ण नीतिगत निहितार्थ सामने आता है। पहली बात तो यह है नीति निर्माताओं को अपने कार्यों

**चित्र 15: निवेश वृद्धि और आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक**



स्रोत: <http://www.policyuncertainty.com/>, CSO

को पूर्वानुमान योग्य करना है, नीति की स्थिति पर आगे मार्गदर्शन करना है और नीति के कार्यान्वयन में अस्पष्टता/मध्यस्थता कम करना है। दूसरा यह कि उपायों पर कार्य करना है। इसलिए आर्थिक नीति अनिश्चितता का सूचकांक का पता तिमाही आधार पर शीर्षतम स्तर पर लगाया जाए। अंततः नीति निर्माण में प्रक्रिया की गुणवत्ता की सुनिश्चितता का अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन के माध्यम से सरकार में कार्यान्वयन हो।

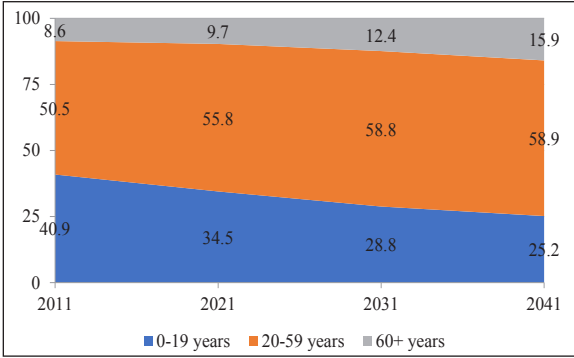
## महत्वपूर्ण संवाहक, सुधार एवं जोखिम कारक

### “सद्चक्र काल” में जनसंख्या की भूमिका

1.47 जैसाकि हम इस सर्वे के भाग 1 के अध्याय 7 में चर्चा करेंगे, भारत कार्यकारी आयु जनसंख्या के अधि कतम हिस्से के इस जनसंख्या चरण में पहले ही पहुंच चुका है। और इस “जनसंख्या भाग” में अगले दो दशकों तक रहेगा। चित्र 16, वस्तुतः यह दर्शाता है कि कार्यकारी आयु जनसंख्या (20-59 वर्ष) जिसका हिस्सा 2011 में कुल जनसंख्या का 50.5 प्रतिशत था, 2041 में बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत हो जाएगा।

1.48 जनांकीय बदलाव, विशेष तौर पर जनसंख्या की आयु संरचना 1960 और 1990 के बीच संपूर्ण एशिया में आर्थिक विकास पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता हुआ दर्शाया गया है (ब्लूम विलियम्सन, 1998)। प्रजनन दर में गिरावट द्वारा आकलित कार्यकारी आयु जनसंख्या के हिस्से में वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है क्योंकि

**चित्र 16: भारत में जनसंख्या संघटन (2011-2041)**



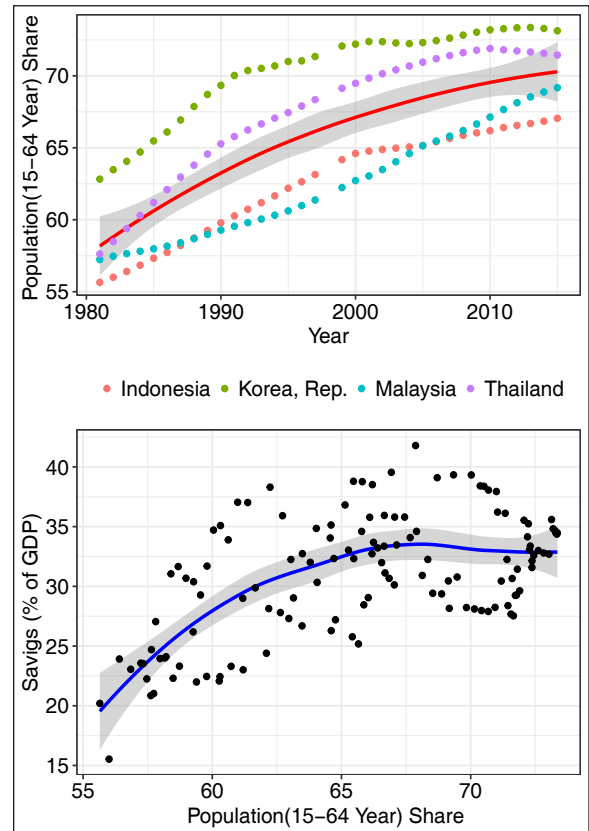
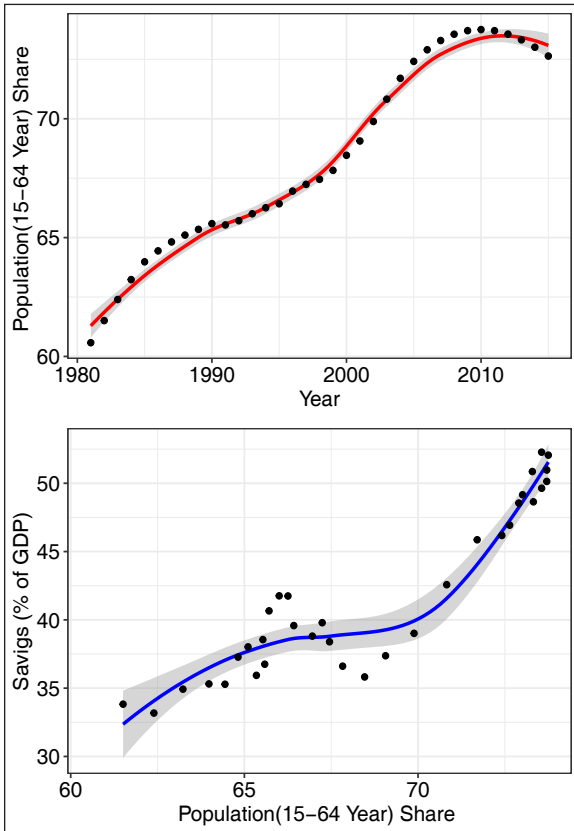
स्रोत: सर्वेक्षण से प्राप्त परिकलन

प्रति कामगार उत्पादन अपरिवर्तित होता है, परन्तु युवा आश्रितों की संख्या घट जाती है। एशिया में कार्यकारी आयु के हिस्से में वृद्धि के कारण यह लेखांकन प्रभाव पड़ा, परन्तु इससे व्यवहार में भी बदलाव आया। बचत में वृद्धि हुई क्योंकि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई (ली,

मैसन एंड मिल्लर 2000; ब्लूम, केनिंग, मैन्सफील्ड एण्ड मूर 2007), और इसके परिणामस्वरूप निवेश भी बढ़ा। वस्तुतः प्रति व्यक्ति रम बल की वृद्धि में परिवर्तन, बचत दर में परिवर्तन और निवेश दर में परिवर्तन तीन संभाव्य प्रणालियां हैं जिनसे आर्थिक विकास पर जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है (हिगिन्स एण्ड विलियम्सन, 1997; ब्लूम एण्ड विलियम्सन, 1998)।

1.49 चित्र 17 दर्शाता है कि चीन में बचत दर और पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि पर युवाओं की संख्या का वृद्ध जनसंख्या में बदलने से किस प्रकार प्रभाव पड़ा। लगभग 1967 में, चीन में प्रजनन दर लगभग प्रति महिला 6 बच्चा था। यह 1990 के मध्य में गिरकर 2 से कम हो गया और बच्चों (0-17 वर्ष) का हिस्सा पिता (18-60 वर्ष) के हिस्से के रूप में 0.73 से गिरकर 0.36 हो गया। इसके अलावा जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण प्रति कामगार (आयु 18-60 वर्ष) वृद्धों की संख्या (61-85 वर्ष की आयु) 0.144 से बढ़कर

**चित्र 17: चीन तथा अन्य उच्च वृद्धि पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की बचत पर जनसांख्यिकीय का प्रभाव**



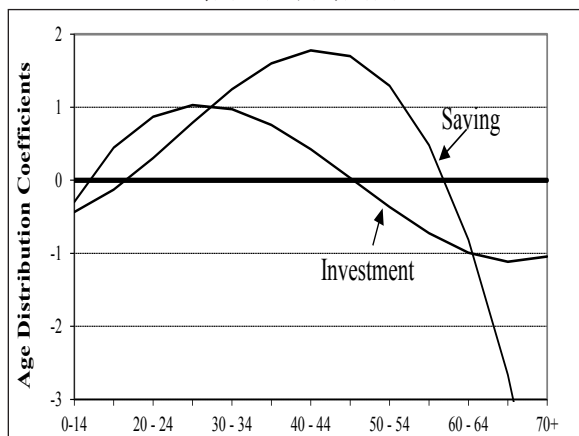
स्रोत: विश्व बैंक

नोट: 1980-2015 की समयावधि को लिया गया है और उच्च वृद्धि वाली अर्थव्यवस्था इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया तथा थाईलैंड से संबंधित है।

0.17 हो गई। सबसे ऊपर बायी ओर का पैनेल दर्शाता है कि चीन में कार्यकारी आयु की जनसंख्या (15-64 वर्ष) में किस प्रकार बदलाव आया जबकि सबसे ऊपर दांयी ओर का पैनेल उच्च वृद्धि दर वाली पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था के लिए भी वही दर्शाता है। निचले पैनेल ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि चीन और उच्च वृद्धि दर वाले पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था में घरेलू बचत दर और जनसंख्या का कार्यकारी आयु अनुपात में किस प्रकार एक साथ वृद्धि हुई। यह समझदारीपूर्ण है क्योंकि केवल लोग ही बचत कर सकते हैं जो पैसा कमाते हैं और अधिकांश लोगों की अधिकांश आय श्रम आय होगी। परन्तु इस जनसंख्या घटक जिनके पास “खिलाने के लिए कम मुंह हों”, उनके पास संसाधनों की उपलब्धता बढ़ जाती है जिसको भविष्य के लिए बचत किया जा सकता है। दूसरा, सेवानिवृत्ति की आय के स्रोत के रूप में बच्चों के महत्व के कारण कार्यकारी पीढ़ी द्वारा बच्चों की संख्या में की गई कमी बचत को प्रोत्साहित करता है क्योंकि वे पिछली पीढ़ी की तुलना में सेवानिवृत्ति के लिए बचत पर अधिक विश्वास करते हैं। अंततः परिवार के संघटन के परिणामस्वरूप भी बचत में वृद्धि होती है क्योंकि अधिकांश बचत 40 से 65 वर्ष की आयु में होती है क्योंकि लोग सेवानिवृद्धि के लिए बचत करना शुरू कर देते हैं।

1.50 जैसाकि एशिया के लिए बोसवर्थ एवं चाउडोरो-रीच (2007) में दर्शाया गया है, कार्यकारी जनसंख्या के अनुपात के साथ बचतों और निवेश में भी वृद्धि होती है (चित्र 18)। ज्ञातव्य हो कि यह चित्र निवेश और बचतों के संबंध में जनसंख्या में प्रत्येक आयु-वर्ग के

चित्र 18: एशिया में बचतों पर जनसंख्या के संघटन का प्रभाव



स्रोत: बोसवर्थ तथा चौडोरो-रीच (2007)।

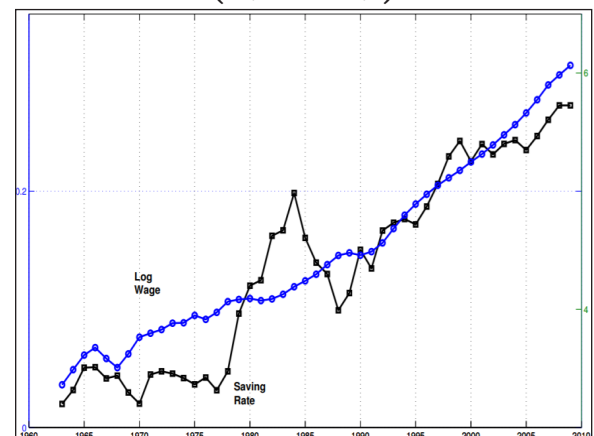
अनुपात को प्रभावित करने वाले सहकारी कारण को दर्शाते हैं। सकारात्मक सहकारी कारण इंगित करता है कि बचतों/निवेश वृद्धि पर आयु वर्ग का प्रभाव पड़ता जबकि नकारात्मक सहकारी कारण यह इंगित करता है कि इसके चलते बचतों/निवेश में कमी आती है। 50 वर्ष की आयु तक प्रत्येक आयु वर्ग में वृद्धि के साथ-साथ निवेश में काफी बढ़त होती है जबकि 60 वर्ष तक प्रत्येक आयु वर्ग में वृद्धि के साथ बचतें बढ़ती हैं।

### वित्तीय सेक्टर की भूमिका

1.51 चित्र 19 में दर्शाता है कि वेतन मजदूरी, चीन की बचत दर को किस प्रकार से प्रभावित करती है। यह संबंध, नोट किए जाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रमजीवी जनसंख्या की आय में वृद्धि/बढ़तीरी किए बिना, न तो उपभोग में वृद्धि होगी और न ही बचत बढ़ेगी। इसीलिए ऐसी जॉब्स अर्थव्यवस्था में बचत दर बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जो अर्थपूर्ण वेतन-मजदूरी दें सके। जिसे हम “सदृशक” कहते हैं, वह एक ओर तो पूंजी और श्रम के मध्य पूरकता का दोहन करके रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करता है तथा दूसरी ओर समग्र उत्पादकता तथा श्रमिकों की उत्पादकता में भी वृद्धि करता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए किए गए नीति संबंध परिवर्तन, इस संदर्भ में नितांत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिन पर हमने सैक्शन 5.2 में विस्तार पूर्वक चर्चा की है।

1.52 इस प्रकार से, हमारा विशेषण दर्शाता है कि बचत प्राथमिकता: जनसांख्यिकी/जनांकिकी तथा आय

चित्र 19: चीन में बचत पर मजदूरी का प्रभाव (1963-2009)



स्रोत: कर्टिस लगाऊर तथा मार्क (2017)।

में वृद्धि द्वारा ही चकित है। इसीलिए बचत करने की प्रवृत्ति का बढ़ावा देने के लिए घरेलू ब्याज दरों को अधिक रखने का कुछ अर्थ नहीं रह जाता वरन एक मामूली सकारात्मक वास्तविक दर ही पर्याप्त है। चूंकि जनांकिकी तथा वेतन/मजदूरी, बचत के मुख्य कारक होते हैं, अतः नीतिनिर्माताओं को काफी हद तक आजादी मिल जाती है। विशेष रूप से, वित्तीय प्रणाली के दो भागों बचतकर्ताओं तथा उधारकर्ताओं को अलग किया जा सकता है। चूंकि निवेश, अत्यावश्यक रूप से पूंजी की कम लागत पर निर्भर करता है अतः जनांकिकी अनुकूल होने पर वास्तविक ब्याज दर कम करने के लिए आवश्यक नहीं है कि बचत कम हो। इसी के साथ-साथ वास्तविक ब्याज दरों में कमी से निवेश को बढ़ावा मिल सकता है तथा तदनुसार निवेश, विकास, निर्यात नौकरियों के लाभकारी चक्र को गति मिलती है

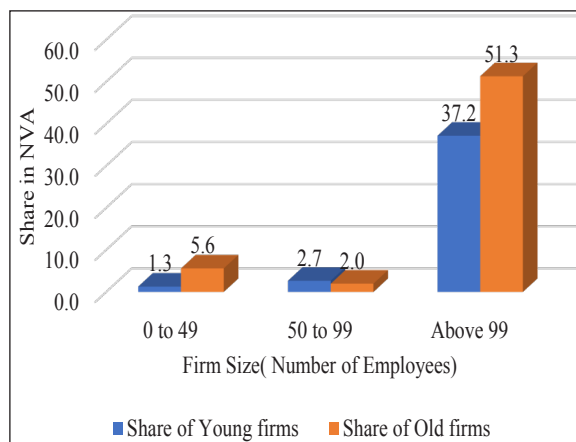
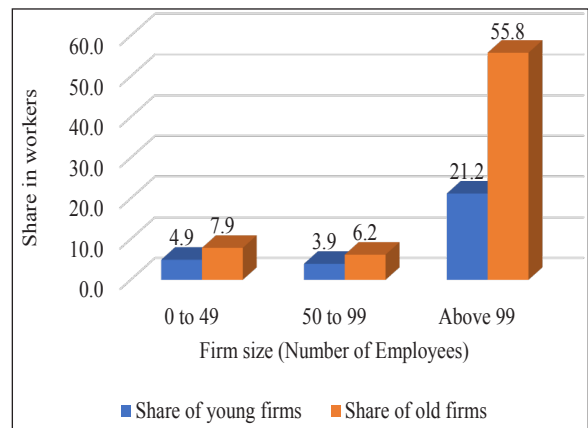
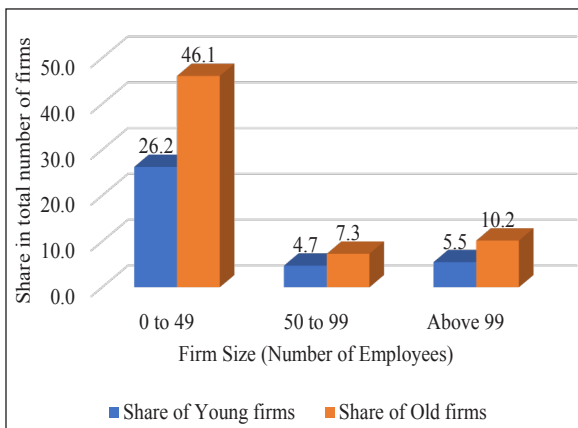
**रोजगार-सृजन और अर्जन ( आमदनी ) की भूमिका**

1.53 सर्वेक्षण के खंड-1 में अध्याय-3 में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बौनी फर्मों, जिसे हम ऐसी

छोटी-फर्मों के रूप में परिभाषित करते हैं जिनका आकार कभी नहीं बढ़ता परंतु ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर हावी होती हैं तथा रोजगार सृजन तथा उत्पादन को रोके रखती हैं। जिन प्रतिष्ठानों/फर्मों में 100 से कम कामगार/श्रमिक नियोजित हैं उन्हें लघु फर्म तथा जिन फर्मों में 100 या अधिक कर्मचारी नियोजित हैं उन्हें अपेक्षाकृत बड़ी फर्मों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि 100 कर्मचारियों को नियोजित करने वाली फर्म निश्चित रूप से वैश्विक संदर्भ में एक बड़ी फर्म नहीं है परंतु भारतीय परिप्रेक्ष्य में वे अपेक्षाकृत बड़ी फर्म ही हैं। ऐसी फर्मों जो छोटी और पुरानी भी हैं तथा दस वर्षों से ज्यादा पुरानी है उन्हें बौनी के रूप में श्रेणी वृद्धि किया गया है क्योंकि ये फर्म 10 वर्षों से अधिक अवधि तक जीवित रहने के बावजूद विकास नहीं कर पाई हैं।<sup>6</sup>

1.54 चित्र-20 कुल फर्मों की संख्या में ड्बार्क की हिस्सेदारी रोजगार में शेयर तथा कुल जोड़े गए सकल मूल्य ( एन.वी.ए. ) में उनका हिस्सा दर्शाता है। यह सर्वेक्षण वर्ष 2016-17 के लिए उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के

**चित्र 20: संख्या, रोजगार एवं उत्पादकता में छोटे एवं अन्य फर्मों का हिस्सा**



स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2016-17 और सर्वेक्षण परिगणना।

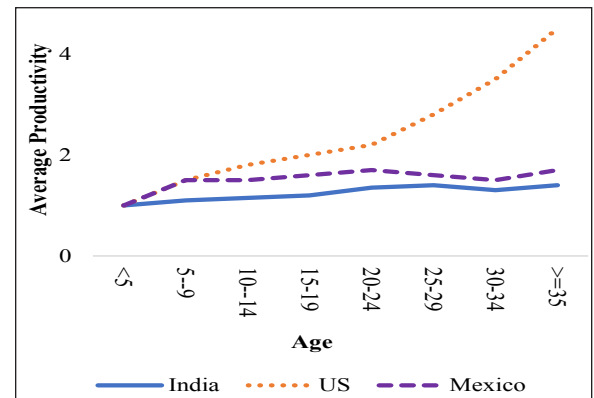
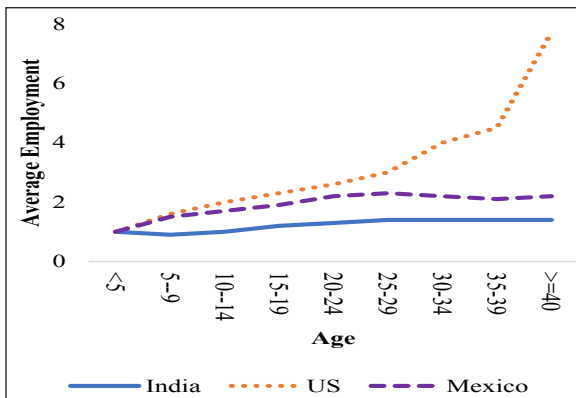
फर्म स्तर के डाटा का उपभोग करते हुए किया गया है जो कि नवीनतम उपलब्ध आंकड़े हैं। हालांकि संगठित क्षेत्र में बौनी फर्मों की संख्या आधी है, रोजगार में उनकी हिस्सेदारी केवल 13.3% ही है। वास्तव में आधे आर्थिक परिदृश्य में वर्चस्व के बावजूद एन.वी.ए. में उनका शेयर केवल 4.7% तक ही सीमित है। इसके विपरीत नवोदित और बड़ी फर्मों (जिसमें 100 से अधिक कर्मचारी हैं) और यह 10 वर्ष से अधिक पुराने नहीं है, संख्या में फर्मों का केवल 6.2% ही है परंतु इसका योगदान एक चौथाई नियोजन और एनपीए का 38% है। बड़े और पुराने फर्म (ऐसे फर्म जिसमें 100 से अधिक कर्मचारी हैं) और यह 10 वर्ष से अधिक पुराने नहीं है। का योगदान संख्या में फर्मों का केवल 9.5% है परंतु रोजगार एवं एनवीए के रूप में इसका योगदान आधा है। इस तरह से ऐसे फर्म जो समय के साथ विकसित होने में समर्थ हैं और बड़े फर्म का रूप ले सकते हैं का योगदान अर्थव्यवस्था में रोजगार और उत्पादन के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है। इसके विपरीत ऐसे भी फर्म हैं जो काफी पुराने होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में रोजगार और उत्पादकता के क्षेत्र में योगदान प्रति व्यक्ति सबसे कम रहा।

1.55 अन्य देशों से तुलना करने पर यह अध्याय दर्शाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 40 वर्ष पुरानी एक औसत फर्म सात गुना से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देती है। जबकि तुलनात्मक रूप से 05 वर्ष पुरानी औसत फर्म

में नियोजित कामगारों की संख्या कम होती है। मेक्सिको में 05 वर्ष से कम अवधि वाली औसत फर्म में नियोजित किए गए कामगारों की तुलना में 40 वर्ष पुरानी फर्म में नियोजित कामगारों की संख्या दोगुनी होती है। इसके विपरीत भारत में 05 वर्ष पुरानी औसत फर्म में नियोजित कामगारों की तुलना जब 40 वर्ष पुरानी औसत फर्म में नियोजित कामगारों से करते हैं तो यह पाते हैं कि 40 वर्ष पुरानी औसत फर्म में मात्र 40% से अधिक कामगार ही नियोजित हैं। अतः भारत में फर्म इतने विकसित नहीं हो पाते हैं कि अर्थव्यवस्था में अपेक्षित रोजगार और उत्पादकता का सृजन कर सकें (चित्र 21)।

1.56 समीक्षा का अध्याय 3 रेखांकित करता है कि प्रतिबंधात्मक श्रम विनियमों जो फर्मों को ऐसे विनियमों से छूट प्रदान करते हैं और अन्य आकार आधारित प्रोत्साहन जो एमएसएमई को लाभ प्रदान करते हैं चाहे इनकी आयु कुछ भी क्यों न हो, ने फर्मों को भारतीय आर्थिक परिदृश्य में काफी छोटा बने रहने के लिए त्रुटिपूर्ण प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यह अध्याय नवोदित फर्मों यानी ऐसी फर्म जिनकी आयु 10 वर्ष से कम हो, को एमएसएमई को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की मौजूदा पद्धति का समुचित संरक्षण प्रदान करते हुए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों पर फोकस करने की संस्तुति करता है। साथ ही यह अध्याय राजस्थान में श्रम कानून में परिवर्तनों के साथ रेखांकित करता है कि प्रतिबंधात्मक श्रम विनियम में सुधार से राज्यों में रोजगार

चित्र 21: भारत, मेक्सिको और अमेरिका में फर्मों की आयु के साथ उनके संबंध में रोजगार एवं उत्पादकता का विकास



स्रोत: शी और क्लेनौ (2014)।

टिप्पणी: Y-अक्ष के 05 वर्ष से कम आयु के समय औसत नियोजन/सकल मूल्य वर्धित के गुणांक के रूप में प्रत्येक आयु समूह में औसत नियोजन/सकल मूल्य वर्धित को दर्शाता है।

<sup>5</sup> प्रत्याख्यान: समीक्षा फर्मों के लिए "बौना" शब्द का उपयोग करती है जोकि 'शिशु' की तुलना में पुरानी होने के बावजूद छोटी बनी रही। वे जो युवा है। यह उपयोग केवल संस्थाओं के लिए है तथा व्यक्ति के लिए ऐसे उपयोग से कोई सहसंबंध नहीं है। अतः किसी संवेदनशीलता को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है।

सूजन और पूंजी संचय को प्रोत्साहित किया जा सकता है। श्रम कानून परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निवेश का संवर्धन कर सकते हैं। (सुब्रमण्यम, और तुंग, 2016; सुब्रमण्यन और मैगिन्शन, 2018)

### वित्तीय क्षेत्र की भूमिका

1.57 निवेश आधारित विकास मॉडल का अर्थ है बैंकों और पूंजी बाजार दोनों का विकास करके वित्तीय प्रणाली में तेजी से विस्तार करना। बदले में, इससे यह जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है कि कोई भी बड़ा वित्तीय संकट इस तरह के त्वरित विस्तार को बाधित कर सकता है, जिससे बचत-निवेश डॉयनामिक पटरी से उतार सकती है। वर्ष 1997-98 के एशियाई संकट के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि यह व्यर्थ की चिंता नहीं है। नब्बे के दशक में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ दक्षिण-पूर्व एशियाई देश पूर्वी एशियाई चमत्कार को पुनः दोहराने वाले थे, लेकिन बड़े पैमाने पर पूंजी के दुरुपयोग के कारण वे लाभ चक्र को बनाए रखने में असमर्थ रहें। 2006 से 2012 तक तेजी से ऋण विस्तार का हमारा अपना अनुभव उसी जोखिम को दर्शाता है, जहां मात्रा का विस्तार होने पर क्रेडिट की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ती जाती है। इस संदर्भ में, बैंकों में पारदर्शिता लाने और दिवालियापन की प्रक्रिया निर्धारित करने के हाल के प्रयासों को एक ऐसे मूल्यवान निवेश के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसे पूरा किया जाना आवश्यक है। यदि भारत ने पांच साल

पहले तेजी से विस्तार करने का प्रयास किया होता तो निश्चित रूप से कुछ वर्षों से उसे एक बड़े वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता। यद्यपि यह कठिन प्रतीत होता है तथापि बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता और आईबीसी फ्रेमवर्क ऐसे महत्वपूर्ण कदम है, जिनसे उस समय लाभ प्राप्त होगा, जब निवेश-संचालित विकास मॉडल को गति दी जाएगी, क्योंकि प्रोत्साहन से ऋण देने की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। (सरकार, सुब्रमण्यन और तंत्री, 2019)।

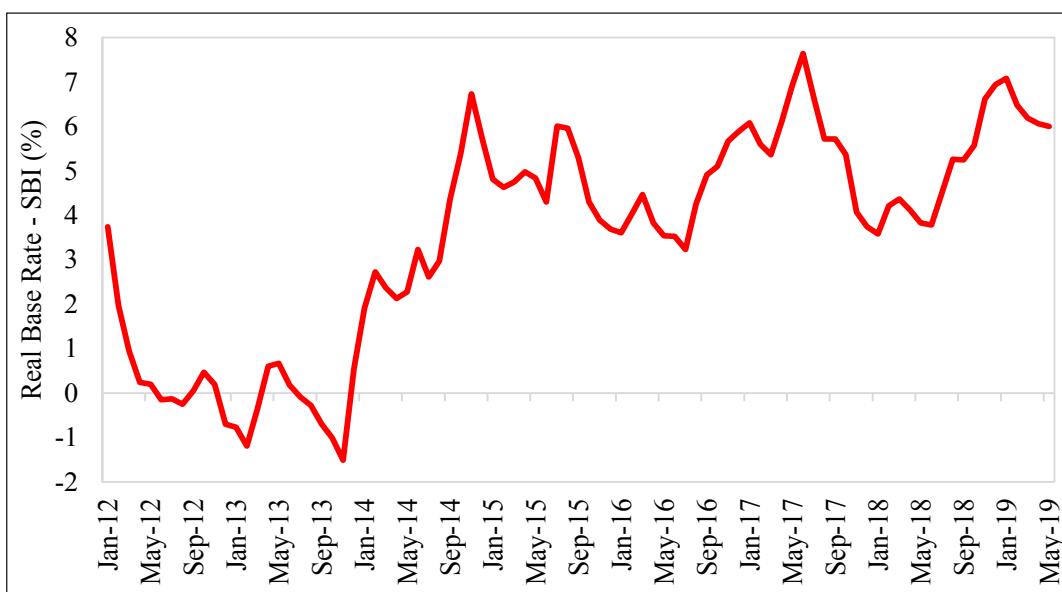
1.58 जबकि विस्तार की नींव रखी जा चुकी है, अब समय है कि पूंजी लागत को काफी कम किया जाए। चित्र 22 में दर्शाया गया है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत में वास्तविक ब्याज दरों में कितनी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वास्तव में विभिन्न देशों से तुलना दर्शाती है कि भारत में पूंजी-लागत काफी अधिक रहती है (चित्र 23 देखें) जो देश में निवेश संभावनाओं को प्रभावित करती है।

### अर्थव्यवस्था में आय-जोखिम के बीच संबंध

1.59 एक अन्य पहलू जो वृद्धि, रोजगार और निर्यातों के लिए बचत-निवेश संचालित मॉडल को बाधित करता है, वह है अर्थव्यवस्था में जोखिम उठाने के लिए प्रचलित प्रोत्साहन संरचना। निवेश के संबंध में आय-जोखिम के बीच के संबंध पर ध्यान दिए जाने का आवश्यकता है।

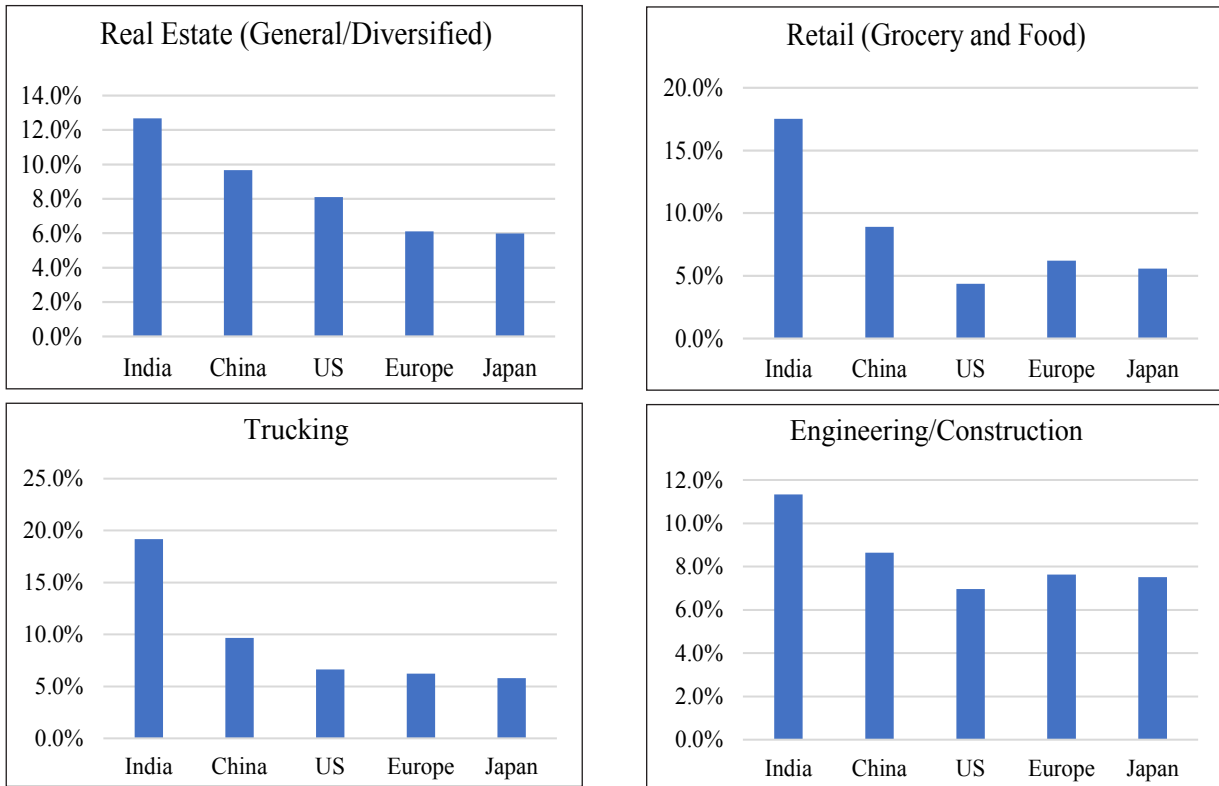
1.60 चूंकि निवेश दूरदेशी कार्यकलाप को दर्शाता है,

चित्र 22: वास्तविक ब्याज दरें (जनवरी 2012-मई-2019)



स्रोत: भारतीय स्टेट बैंक तथा सर्वेक्षण गणनाएं।

चित्र 23: कुछ क्षेत्रों में पूंजी लागत की विभिन्न देशों में तुलना



स्रोत: दामोदरन (2019)

इसलिए निवेशक जितनी जोखिम-समायोजित आय की आशा करते हैं, उसी के आधार पर निवेश करने का स्वयं का निर्णय करते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि दो परियोजनाओं में बिल्कुल एक जैसी आय होती है, किन्तु उनमें से एक परियोजना में जोखिम ज्यादा है, तो निवेशक निवेश हेतु उसी परियोजना में निवेश करेंगे जिससे जोखिम कम है। इस प्रकार, आर्थिक वृद्धि के लिए निवेश संचालित मॉडल की सफलता के लिए निवेशकों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम को कम किया जाना महत्वपूर्ण है। जोखिम का मतलब हुआ कि सफलता की संभावनाएं यदि परियोजना का कार्यनिष्पादन बेहतर होता है और असफलता यदि परियोजना का कार्यनिष्पादन बेहतर होता है और असफलता यदि परियोजना विफल हो जाती है। अतः, इस संबंध में आईबीसी का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है क्योंकि कारोबार विफल होने पर यह परिसंपत्तियों को पुनः आकार देने के लिए रूपरेखा को प्रक्रिया में लाता है। तथापि, कर-पश्चात् आय महत्वपूर्ण रूप से निवेश संबंधी आय-जोखिम संबंध को प्रभावित करता है और इसलिए यह निवेश बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है।

1.61 इस संबंध में इष्टतम कर नीति अहम भूमिका निभाती है। विश्वभर में देश अस्थायी व्यापार के पुनर्स्थापन को लक्षित करने के लिए कर प्रोत्साहनों को सिर्फ उपाय न मान कर नवाचार के लिए केन्द्र सृजित करने हेतु उन्हें माध्यम बनाने के लिए कर प्रोत्साहनों को विकसित करने को मान्यता देते हैं। पूंजी और व्यापार एंजल के जोखिम के लिए कर प्रोत्साहनों को यदि ठीक प्रकार से संदर्भ के अनुसार अभिकल्पित और बनाया जाए तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप्स के निवेश को बढ़ा सकते हैं (यूरोपीय आयोग, 2017)। अतः, अर्थव्यवस्था में नवाचार निवेशों को बढ़ाने के लिए कर नीति और इसके कार्यान्वयन को स्टार्टअप्स के लिए औचित्यपूर्ण बनाया जाना अत्यावश्यक है। कई अध्ययनों से भी पता चला है कि पूंजीगत लाभ को और अधिक जोखिम भरे निवेशों में उपयोग करने के लिए इसके लॉक-इन प्रभावों तथा संबद्ध निरुत्साहित करने वाले प्रोत्साहनों के संदर्भ में व्यक्ति निवेशकों के लिए पूंजीगत लाभ कर के महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम हो सकते हैं (मीड, 1990)। इष्टतम कर नीति अभिकल्प का लक्ष्य राजस्व दक्षतापूर्वक और न्यायपूर्ण से उगाहना है और यह प्रमाणिक करदाताओं को प्रोत्साहित करके तथा दुर्भावनापूर्ण करदाताओं को

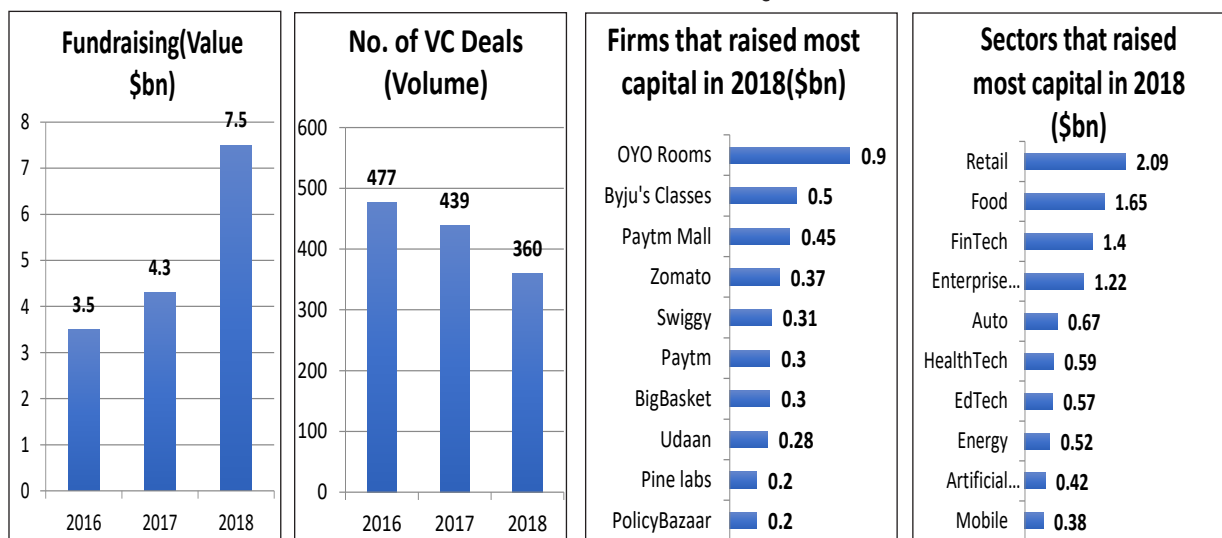
दंडित करके किया जाए। तथापि, इष्टतमता हासिल करना कोई सरल कार्य नहीं है। फिर भी, निवेश में वृद्धि के लिए, भारतीय संदर्भ में इसका सही संतुलन प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

1.62 नई अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि को, ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र के जो नवाचार व उद्यमिता को पुरस्कृत करता हो, के बिना गतिशील बनाना संभव नहीं है। पारंपरिक “ईट व गारे” से बनी कंपनियों की अपेक्षा स्टार्टअप्स तथा नवाचार उद्यम महत्वपूर्ण रूप से कहीं अधिक अनिश्चितता का सामना करते हैं। फिर भी, जैसाकि नवंबर 2019 में एंजल कर के वाक्ये से ज्ञात हुआ (जिसका समाधान हो चुका है), नीति में अस्पष्टताएं जो जोखिम उठाने वाले वास्तविक निवेशकों के लिए

संपार्श्विक क्षति सृजित करती हैं, अर्थव्यवस्था में लोगों को निरुत्साहित करके निवेशों को प्रभावित करती हैं।

1.63 स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी में विश्व में तीसरे पायदान पर, भारत में घरेलू उद्यमों को ऐसी बढ़ती जमात है जो शहरी चुनौतियों का प्रबंधन करने और समाधान निकालने की ओर लक्षित समाधानों को विकसित कर रहे हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर तकनीकी स्टार्ट-अप्स है जो ई-कॉमर्स तथा उपभोक्ता उत्पादों और सेवाओं से संबंधित हैं, वर्ष 2018 को खाद्य स्टार्ट-अप्स के तौर पर माना गया था। चित्र 24 उस सांख्यिकी को दर्शाता है जो भारत में विकसित जीवंत स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी को दर्शाता है। सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी तथा चालन संबंधी दक्षताओं को सुगम बनाने से संबंधित स्टार्ट-अप, चाहे

चित्र 24: भारत के स्टार्ट-अप्स की प्रवृत्ति (2018)



Company	Total Funding(\$bn)	Post-money valuation(\$bn)	Time taken to become an unicorn(yrs) (RHS)
Flipkart	6.1	15.51	3
OYO Rooms	1.35	4.18	5
Ola	2.8	4	2
Byju's Classes	0.74	3.02	4
Snapdeal	1.8	2.47	3
Paytm Mall	0.653	2.01	Less than 1
Zomato	0.58	2	5
Swiggy	0.46	1.21	3
Quikr	0.37	0.88	7
PolicyBazaar	0.37	0.44	10

Company	Total Funding(\$bn)	Post-money valuation(\$bn)
Rivigo	0.17	0.92
Billdesk	0.16	0.83
BookMyShow	0.23	0.78
BigBasket	0.56	0.72
Delhivery	0.26	0.60
Sharechat	0.12	0.50
UrbanClap	0.11	0.47
CarDekho	0.28	0.45
CarTrade	0.25	0.40
CapitalFloat	0.11	0.35

Target	Acquired by	Value (\$bn)
Flipkart	Walmart	16
Embibe	RIL	0.18
Saavn	RIL	0.10
Ridlr	Ola Cabs	0.05
Minjar	Nutanix	0.05
Mettl	Mercer	0.40
TicketNew	PayTm	0.40
Liv.ai	Flipkart	0.40
Tapzo	Amazon	0.40
Walnut	CapitalFloat	0.30

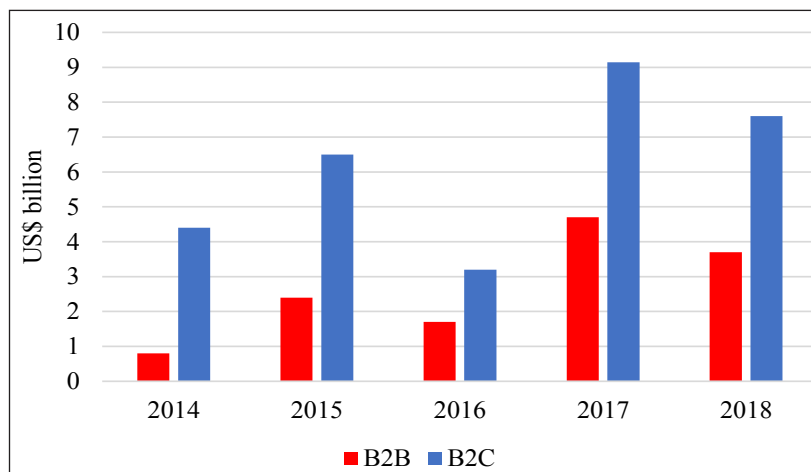
स्रोत: सरकार (2018)।



वे अपशिष्ट, जल अथवा ऊर्जा के रूप में निर्मित हों, धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से उभर रहे हैं। चित्र 25 इसी तथ्य को रेखांकित करता है क्योंकि बी2सी स्टार्ट-अप द्वारा प्राप्त निधियन बी2बी स्टार्ट-अप द्वारा प्राप्त निधियन से कहीं अधिक है।

1.64 विशेष रूप से नई अर्थव्यवस्था में निजी निवेश के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण जारी रखना इसलिए महत्वपूर्ण है कि सद्चक्र को सक्षम करने के लिए निवेश, निर्यात, विकास एवं नौकरियों की आवश्यकता है।

चित्र 25: बी2बी स्टार्टअप्स में निधियन बी2सी स्टार्ट-अप्स की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ रहा है



स्रोत: गोयल (2019)।

## अध्याय: एक नजर में

- पिछले पांच वर्षों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ऊपर से नीचे की ओर हितलाभ संचरण के कई रास्ते खोल कर, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि समष्टि आर्थिक स्थिरता के लाभ पिरामिड के निचले स्तर तक पहुंचें।
- वर्ष 2024-25 तक पांच ट्रिलियन अमेरिकी डालर वाली अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्य को पाने के लिए भारत को 8 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर को बनाए रखना होगा। अंतरराष्ट्रीय, विशेषकर उच्च संवृद्धिशील पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्था के अनुभव बताते हैं कि ऐसी संवृद्धि को बचत निवेश और निर्यात का सद्चक्र ही बनाए रख सकता है यदि उसे अनुकूल जनांकीय सोपान का सहयोग भी मिल जाए। निवेश, विशेषकर निजी निवेश, एक प्रमुख चालक है जो कि मांग, क्षमता निर्माण, श्रम उत्पादकता वृद्धि का प्रचालक होता है और नई प्रौद्योगिकी का प्रवर्तक होता है जो रचनात्मक विध्वंस तथा रोजगार सृजन की अनुभव प्रदान करता है।
- निर्यात को संवृद्धि प्रतिमान का अभिन्न अंग होना ही चाहिए क्योंकि उच्चतर बचत के कारण आन्तरिक उपभोग, अंतिम मांग का प्रचालक नहीं बन पाता। इसी प्रकार रोजगार सृजन भी सहचक्र से संचालित होता है। प्रायः दावा किया जाता है कि निवेश रोजगार का प्रतिस्थापक बन जाता है—यह किसी गतिविधि विशेष के संदर्भ में ही ठीक होता है यदि संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को देखा जाए तो पूर्वी निवेश रोजगार बढ़ाते हैं क्योंकि पूंजीगत पदार्थों का उत्पादन, शोध और विकास तथा आपूर्ति श्रृंखला भी रोजगार वृद्धि में सहायक हैं।
- उपर्युक्त संवृद्धि प्रतिमान की अभिकल्पना करते हुए समीक्षा परंपरागत ऐंग्लो सेक्सन चिन्तन से दूर हट रही है और मान रही है कि अर्थव्यवस्था या तो सद्चक्र या दुश्चक्र से, प्रस्त होती है तथा संतुलन में कभी नहीं होती।
- आंकड़ों को सार्वजनिक पदार्थ के रूप से प्रस्तुत करके, विधिक सुधारों पर जोर देकर, नीतिगत सुसंगति सुनिश्चित करके तथा व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र के नियमों के अनुरूप व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करके, समीक्षा एक स्वपोषित सद्चक्र को प्रारंभ करने का लक्ष्य लिए हुए है। मुख्य तत्वों में उन नीतियों पर ध्यान देना शामिल है जो एमएसएमई उद्यमों का पोषण कर उन्हें अधिक रोजगार सृजित करने, उत्पादन बढ़ाने, पूंजी की लागत घटाने में सक्षम और निवेश पर जोखिम-प्रतिप्राप्ति के सम प्रत्ययन को तर्क संगत बनाती हैं।

## संदर्भ

- Acharya, Viral V. and Krishnamurthy V. Subramanian. 2009. "Bankruptcy Codes and Innovation," *The Review of Financial Studies*, 22(12), 4949-4988.
- Acharya, Viral, Ramin, Baghai and Krishnamurthy V. Subramanian. 2013. "Labor Laws and Innovation," *Journal of Law and Economics*, 56(4), 997-1037.
- Acharya, Viral, Ramin, Baghai and Krishnamurthy V. Subramanian. 2014. "Wrongful Discharge Laws and Innovation," *The Review of Financial Studies*, 27(1).
- Attanasio, Orazio P., Lucio Picci, and Antonello E. Scorcu, 2000. "Saving, Growth, and Investment: A Macroeconomic Analysis Using a Panel of Countries," *The Review of Economics and Statistics* 82(2):182-211.
- Baker, Scott R., Nicholas Bloom, and Steven J. Davis. 2016. "Measuring Economic Policy Uncertainty." *The Quarterly Journal of Economics* 131(4): 1593-1636.
- Bloom, David E., and Jeffrey G. Williamson. 1998. "Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia." *The World Bank Economic Review* 12(3): 419-455.
- Bloom, David E., David Canning, Richard K. Mansfield, and Michael Moore. 2007. "Demographic change, social security systems, and savings." *Journal of Monetary Economics* 54(1): 92-114.
- Bosworth, Barry, and Gabriel Chodorow-Reich. 2007. "Saving and Demographic Change: The Global Dimension." SSRN. <https://ssrn.com/abstract=1299702>.
- Carroll, Christopher D., and David N., Weil. 1994. "Saving and growth: a reinterpretation." *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 40(1): 133-192.
- Chakrabarti, Rajesh, Krishnamurthy V. Subramanian and Sessa Meka. 2017. "Localization of FDI flows: Evidence on Infrastructure as a critical determinant of FDI," *Journal of Law, Finance and Accounting*, 2(1), 205-246.
- Chava, S., Alexander Oettl, Ajay Subramanian and Krishnamurthy V. Subramanian. 2013. "Banking Deregulation and Innovation," *Journal of Financial Economics*, 109(3), 759-774.
- Curtis, Chadwick C., Steven Lugauer, and Nelson C. Mark. 2011. "Demographic Patterns and Household Saving in China." *American Economic Journal: Macroeconomics* 7(2): 58-94.
- Curtis, Chadwick C., Steven Lugauer, and Nelson C. Mark. 2017. "Demographics and aggregate household saving in Japan, China, and India." *Journal of Macroeconomics* 51(C):175-191.
- Damodaran, Aswath. 2019. "Data: Current." Damodaran Online(blog), January 5. [http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New\\_Home\\_Page/datacurrent.html](http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datacurrent.html).
- European Commission. *Effectiveness of tax incentives for venture capital and business angels to foster the investment of SMEs and start-ups*. Brussels: European Commission, 2017. [https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/sites/taxation/files/final\\_report\\_2017\\_taxud\\_venture-capital\\_business-angels.pdf](https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/final_report_2017_taxud_venture-capital_business-angels.pdf).
- Feldstein, Martin, and Charles Horioka. 1980. "Domestic saving and international capital flows." *Economic Journal* 90(358): 314-329.
- Fu, Xiaolan, and V. N. Balasubramanyam. 2005. "Exports, foreign direct investment and employment: The case of China." *World Economy* 28(4): 607-625.
- Gourinchas, Pierre-Olivier, and Olivier

- Jeanne. 2013. "Capital Flows to Developing Countries: The Allocation Puzzle." *The Review of Economic Studies* 80(4):1484-1515.
- Goyal, Malini. 2019. "How the centre of gravity of India's startup ecosystem is shifting towards B2B startups." *Economic Times*, March 2019. <https://economictimes.indiatimes.com/small-biz/startups/features/how-the-centre-of-gravity-of-indias-startup-ecosystem-is-shifting-towards-b2b-startups/articleshow/68235644.cms?from=mdr>
- Haskel, Jonathan E., Sonia C. Pereira, and Matthew J. Slaughter. 2007. "Does inward foreign direct investment boost the productivity of domestic firms?" *The Review of Economics and Statistics* 89(3): 482-496.
- Hayek, Friedrich August von. 1974. "The Pretence of Knowledge." Prize Lecture, The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. <https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1974/hayek/lecture/>.
- Higgins Matthew, and Jeffrey .G. Williamson. 1997. "Age structure dynamics in Asia and dependence on foreign capital." *Population and Development Review* 23 (2): 261-293.
- Hsieh, Chang-Tai, and Peter J. Klenow. 2014. "The Life Cycle of Plants in India and Mexico." *The Quarterly Journal of Economics* 129(3): 1035-1084.
- Jin, Keyu. 2012. "Industrial Structure and Capital Flows." *American Economic Review* 102 (5), 2111-46.
- Lee, Ronald, Andrew Mason, and Tim Miller. 2000. "Life Cycle Saving and the Demographic Transition: The Case of Taiwan." *Population and Development Review* 26: 194-219.
- Lin, Jeffrey. 2011. "Technological Adaptation, Cities, and New Work." *Review of Economics and Statistics* 93(2): 554-74.
- Lucas, Robert. E. Jr. 1990. "Why doesn't capital flow from rich to poor countries?" *American Economic Review* 80(2): 92-96.
- Meade, Janet A. 1990. "The Impact of Different Capital Gains Tax Regimes on the Lock-In Effect and New Risky Investment Decisions." *The Accounting Review* 65(2): 406-431.
- Milkman, Katherine L., Mary Carol Mazza, Lisa L. Shu, Chia-Jung Tsay, and Max H. Bazerman. 2012. "Policy Bundling to Overcome Loss Aversion: A Method for Improving Legislative Outcomes." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 117(1): 158-167.
- Perotti, Enrico C., Laixiang Sun, and Liang Zou. 1999. "State-Owned versus Township and Village Enterprises in China." *Comparative Economic Studies* 41:1-20.
- Ramos, Gabriela. 2017. "We need an empowering narrative." OECD Insights (blog), June 23. <http://oecdinsights.org/2017/06/23/we-need-an-empowering-narrative/>.
- Rodrik, Dani. 2000. "Savings Transitions." *World Bank Economic Review* 14(3): 481-507.
- Rodrik, Dani. 2018. "Second thoughts on economics rules." *Journal of Economic Methodology* 25(3): 1-6.
- Romer, Paul. 2015. "Mathiness in the theory of economic growth." *American Economic Review* 105(5):89-93.
- Sandri, Damiano. 2014. "Growth and capital flows with risky entrepreneurship." *American Economic Journal: Macroeconomics* 6(3): 102-123.
- Sapra, H., Ajay Subramanian and

Krishnamurthy V. Subramanian. 2014. "Corporate Governance and Innovation: Theory and Evidence," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 49(4), 957 – 1003.

Sarkar, Ranju. 2018. "With record capital raising, 2018 was year of transformation for start-ups." *Business Standard*, December 2018. [https://www.business-standard.com/article/companies/with-record-capital-raising-2018-was-year-of-transformation-for-start-ups-118122900674\\_1.html](https://www.business-standard.com/article/companies/with-record-capital-raising-2018-was-year-of-transformation-for-start-ups-118122900674_1.html).

Sarkar, A., Krishnamurthy V. Subramanian and Prasanna Tantri. 2019. "Effects of CEO Turnover in Banks: Evidence Using Exogenous Turnovers in Indian Banks," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 54(1), 183-214.

Subramanian, Krishnamurthy V. 2011. Lessons from the financial crisis: failure

of markets or failure of regulation? *Macroeconomics and Finance in Emerging Market Economies*, 4(2).

Subramanian, Krishnamurthy V. and William Megginson, 2018. "Employment Protection Laws and Privatization," *Journal of Law and Economics*, 61(1), 97-123.

Subramanian, Krishnamurthy V. and Frederick Tung, 2016. "Law and Project Finance," *Journal of Financial Intermediation*, 25(1), 154-177.

Wei, Yingqi, and V. N. Balasubramanyam. 2015. "A Comparative Analysis of China and India's Manufacturing Sectors." Economics Working Paper Series 2015/003. Lancaster University Management School. [https://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/contentassets/documents/lums/economics/working-papers/LancasterWP2015\\_003.pdf](https://www.lancaster.ac.uk/media/lancaster-university/contentassets/documents/lums/economics/working-papers/LancasterWP2015_003.pdf).